आज का विचार

जिंदगी भी एक
अनजान किताब
जैसी है अगले पन्ने
पर क्या लिखा है
किसी को नहीं पता।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

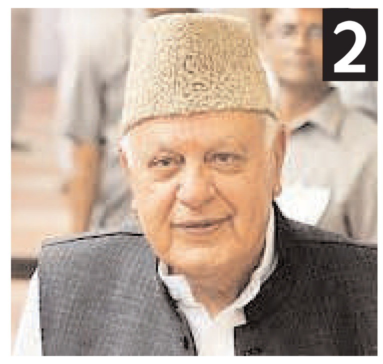

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | शनिवार, 6 दिसंबर, 2025 वर्ष 23, अंक 308, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

हरियाणा खेल मॉडल वैश्विक नेतृत्व का बनेगा आधार: नायब सिंह सैनी

खेलों में भारतीयकरण का आधार चार एम — आधुनिकता, मानसिकता, प्रबंधन और नैतिक बेहद कारगर साबित होंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में आयोजित ह्लआधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडलऱ कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल आज केवल खिलाड़ियों तक सीमित विषय नहीं रह गया, बल्कि यह एक विशाल रोजगार, नवाचार और विज्ञान-आधारित क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने देशभर से आए शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के खेल क्षेत्र का एक मजबूत रोडमैप तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य में खेल क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर राज्य की पहचान को नई ऊंचाई दी है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खेल क्षेत्र में 989 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जबकि इस वित्त वर्ष के बजट में 589 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आज राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 382 इंडोर जिम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा

कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटरों और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1,489 खेल नर्सरियां संचालित हो रही हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक भारतीय खेल तकनीकों को आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर भारत एक नया ह्लइंडियन स्पोर्ट्स ब्रांडह्व तैयार कर सकता है, जो देश के खेल मॉडल को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खिलाड़ियों की प्रतिभा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आधुनिक प्रबंधन के समन्वय से भारत 2026 और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में उल्लेखनीय सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस भारत के खेल भविष्य को नई दिशा देने वाली है। यहां रखे गए विचार आने वाले वर्षों में भारत के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगे। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ह्लविकसित भारतह्व के संकल्प को खेलों के माध्यम से मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने ह्लआधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडलऱ पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन खेलों में नवाचार को बढ़ावा देगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति व पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस दो दिवसीय सेमिनार का उद्देश्य खेलों में भारतीय संस्कृति के समावेश को शामिल करना है। उन्होंने वर्ष 2022 में स्थापित खेल विश्वविद्यालय की उपलब्धियां पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, राई से विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत से विधायक निखिल मदान, विधायक पवन खरखोदा, मेयर राजीव जैन, अंतरराष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भारत और रूस 2030 तक आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत

प्रधानमंत्री बोले-ध्रुव तारे की तरह अटल है रिश्ते

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत और रूस ने 2030 तक के आर्थिक रोडमैप की घोषणा करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें तय की हैं। रूस में भारतीय फार्मा फैक्टरी स्थापित की जाएगी, जबकि भारत में संयुक्त रूप से यूरिया उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रूस भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण में सहयोग देगा और जहाजरानी एवं शिपबिल्डिंग में साझेदारी को मजबूत बनाएगा। रूस ने भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। रूसी नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा दी जाएगी और लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए मोबिलिटी पैक्ट पर सहमति बनी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हैदराबाद हाउस में लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को फिर से पक्का किया। उन्होंने आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के समक्ष कई समझौता का आदान प्रदान हुआ। यह व्यापार-वाणिज्य, प्रवासन और आवाजाही, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, शिक्षा से जुड़े आदान-प्रदान, मीडिया सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने से जुड़े विषय शामिल हैं।

वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-रूस संबंधों की तुलना आकाश में एक स्थान पर स्थिर बने रहने वाले ध्रुव तारे से की। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2030 तक अपने आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश यूरेशिया (एशिया-यूरोप) आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत शीघ्र ही रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 दिनों के टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरूआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दुर्लभ खनिजों में दोनों देशों के सहयोग को पूरे विश्व में सप्लाई चैन की सुरक्षित और विविधता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छ ऊर्जा, उच्च तकनीकी उत्पादन और आने वाले समय के उद्योगों में हमारी साझेदारी को समर्थन देंगे। ऊर्जा सुरक्षा को भारत रूस साझेदारी का महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ बताया। नागरिक नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों का दशकों पुराना सहयोग स्वच्छ ऊर्जा की हमारी सामाजिक प्राथमिकता को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

आतंकवाद पर कड़ा रुख जाहिर किया

आतंकवाद पर एक बार फिर कड़ा रुख जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई में भारत-रूस लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्य पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारी मित्रता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को समृद्ध करेगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता में भारत-रूस सहयोग के कई नए आयामों की घोषणा की। पुतिन ने बताया कि रूस में भारतीय तकनीक से एक बड़ी फार्मा फैक्टरी स्थापित की जाएगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन संभव होगा। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है और रूस भारत को तेल, गैस और कोयले की निर्बाध आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आज कई महत्त्वपूर्ण समझौते हुए हैं और प्रमुख परियोजनाओं पर करीबी निगरानी जारी है। पुतिन ने ब्रिक्स में भारत-रूस की साझेदारी को निर्णायक बताते हुए कहा कि अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान रूस पूरा सहयोग देगा। दोनों देश स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, बेलारूस और रूस से भारतीय महासागर तक नए मार्गों के विकास पर भी प्रगति का उल्लेख किया।

सरकार ने उड़ानें रद्द होने के मामले का संज्ञान लिया है: किरेन रिजिजू

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केन्द्र सरकार विमानों की उड़ानें रद्द होने जैसे जनहित के मुद्दों पर निरंतर नजर बनाए हुए है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को बताया कि सरकार इस समस्या पर संज्ञान ले चुकी है और जल्द ही सदन में विस्तृत जानकारी देगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार निजी एयरलाइनों की तकनीकी समस्याओं को लेकर पहल कर रही है। रिजिजू ने उड़ानें रद्द होने संबंधी सवालों पर बताया कि इस बारे में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है।

इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने साफ किया संसदीय एजेंडा (वंदे मातरम और चुनाव सुधार) तय कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) के निर्णयों चुनाव सुधार और 'वंदे मातरम' पर किए गए एक और सवाल के जबाव में रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा मंगलवार को होगी और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि चुनाव सुधारों से संबंधित विषय पर लोकसभा में चर्चा पूरी होने के तुरंत बाद राज्यसभा में चर्चा शुरू की जाएगी।

- उड्डयन मंत्री ने एयरलाइन उड़ानें बाधित होने पर उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश

उधर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन सहित कई एयरलाइन की उड़ानों में व्यापक रुकावट को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) की चार सदस्यीय जांच समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, एसएफओआई कैप्ट. कपिल मंगलीक और एफओआई कैप्ट. लोकेश रांपाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें यात्रियों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 247 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसके लिए उन्होंने संपर्क नं 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859 जारी किए हैं। इस जांच का उद्देश्य इंडिगो की उड़ानें प्रभावित होने की जांच करना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाना है। मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) के उड़ानों के तय समय (एफडीटीएल) के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, छात्रों, मरीजों और जरूरतों के लिए हवाई यात्रा पर निर्भर अन्य लोगों की सहायता के लिए लिया गया है। ंत्री ने आश्वासन दिया है कि सामान्य एयरलाइन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कई परिचालन उपाय किए गए हैं। फ्लाइट शेड्यूल के कल तक स्थिर होने और सामान्य होने की उम्मीद है, जबकि सेवाओं की पूरी बहाली अगले तीन दिनों के भीतर होने की संभावना है। बयान में यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बयान में एयरलाइंस को बेहतर ऑनलाइन सूचना प्रणालियों के माध्यम से नियमित और सटीक अपडेट देने का निर्देश दिया गया है, ताकि यात्री अपने घरों से ही वास्तविक समय में उड़ान की स्थिति की निगरानी कर सकें।

भारतीय रेलवे की समयपालन क्षमता में सुधार, कई डिवीजन 90 प्रतिशत से ऊपर: अश्विनी वैष्णव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे की समयपालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है और पूरे नेटवर्क की समयपालन दर (पंक्चुअलिटी) अब 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है।

रेल मंत्री वैष्णव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि देश के 70 रेल डिवीजन में से 25 डिवीजन ऐसे हैं, जिन्होंने 90 प्रतिशत से अधिक पंक्चुअलिटी दर्ज की है। यह हाल के वर्षों में की गई मजबूत रखरखाव व्यवस्था और व्यवस्थित परिचालन सुधारों का परिणाम है। रेल मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि उन्नत तकनीकों और प्रणालीगत अपग्रेड के कारण ट्रेनों की समय पर संचालन में लगातार सुधार हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेल समयपालन के मामले में कई यूरोपीय देशों के रेलवे नेटवर्क से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उदाहरण के तौर पर, जर्मनी की डॉयचे बान की लंबी दूरी की सेवाओं की समयपालन दर वर्ष 2024 में 67.4 प्रतिशत रही थी, जबकि भारतीय रेलवे इससे काफी आगे निकल चुका है। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संचालन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार, बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट के आधुनिक उपाय लागू किए गए हैं। आने वाले समय में पंक्चुअलिटी को और बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वदेशोत्सव 2025 का किया भव्य उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्वर्णिम जागरण मंच और स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेशोत्सव 2025 का आज शुक्रवार को अहमदाबाद में भव्य शुभारंभ किया गया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी एक्स्पो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह महोत्सव 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक पाँच दिनों तक आयोजित रहेगा।

उद्घाटन के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी सामर्थ्य के प्रतीक रूप में तैयार की गई ह्यसवानुभूति प्रदर्शनीह्ल का भी शुभारंभ किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, जागरूकता और स्वदेशी विचारधारा का प्रसार करना है। इसी उद्देश्य से विविध महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष संगोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन किया गया है।

महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7:00 से 10:00 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान में आयोजित यह आयोजन ज्ञान, कला और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा।

मोदी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, किसानों को ठीक दाम देने का काम किया: शिवराज

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन का उचित दाम किसानों को देने का काम किया है। हमारा एक ही फामूर्ला है- किसानों का कल्याण।

प्रश्न काल में कांग्रेस सदस्य मुकुल वासनिक के प्रश्न के उत्तर में शिवराज ने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीदी कर रहे हैं। कई फसलों पर तो 50 प्रतिशत से ज्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 के पहले इतनी नहीं खरीदी जाती थी और दलहन-तिलहन की फसल के लिए तो 2014 के पहले नाममात्र की खरीदी होती थी। हमने पीएम आशा योजना भी बनाई है।

शिवराज ने कहा कि कई राज्य सरकार खरीदी में ढिलाई करती है, पूरा नहीं खरीदती है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है, वहीं हमने तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द राज्य सरकार अगर कम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो नैफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से सीधे भी हम खरीदने का काम करेंगे, ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। वर्ष 2004 से 2014 के बीच सभी खरीफ की फसले एमएसपी पर केवल 46 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थीं, जबकि मोदी सरकार ने 81 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन खरीदी की हैं। रबी की फसल 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, उस समय जब यूपीए की सरकार थी, वहीं एनडीए की सरकार ने 35 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन खरीदी है और अलग-अलग दलहन और तिलहन की खरीदी भी की। तिलहन 47

लाख 75 हजार मीट्रिक टन खरीदी जाती थी पहले, वहीं एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। दलहन 6 लाख मीट्रिक टन 10 साल में खरीदी गई थी, वहीं हमने 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन खरीदी है और इस तरह से किसानों को उसके उत्पाद का पूरा दाम देने का हमने प्रयास किया है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। हमने एमएसपी तय की, जबकि यूपीए सरकार, 2013-14 में जितनी एमएसपी देती थी, उससे दोगुनी एमएसपी घोषित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। शिवराज ने उपजवार आंकड़े देते हुए बताया कि यूपीए सरकार के समय धान, ज्वार, बाजरा, रागी, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि पर बहुत कम दाम दिए जाते थे, जबकि वर्तमान में एमएसपी काफी बढ़ाकर दी जा रही हैं, साथ ही एमएसपी पर खरीद भी बहुत बढ़ाई गई हैं। उन्होंने तमाम आंकड़ों के साथ यूपीए सरकार के कार्यकाल के समय से तुलना करते हुए विपक्ष पर ताना कसते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।

शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले साल कर्नाटक की सरकार ने 2024-25 में तुअर खरीदने की बात की, तो हमने कर्नाटक की सरकार से कहा था कि 100 प्रतिशत खरीदो। उनका कहना रहा कि 100 प्रतिशत नहीं, हमें केवल 25 प्रतिशत की स्वीकृति दो। तब हमने 25 प्रतिशत की स्वीकृति दी, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं खरीदी। हमने स्वीकृति दी 3,06,150 एमटी की और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने खरीदी 2,16,303 एमटी, जो गारंटी है, उसे भी आपकी सरकारें खरीदती नहीं हैं। शिवराज ने कहा कि इन्होंने तो कोई फामूर्ला माना ही नहीं और हमारा एक ही फामूर्ला है, किसानों का कल्याण। किसानों को उत्पाद के ठीक दाम देना हमारा संकल्प है और किसानों के हित में इस संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे।

अति आधुनिकता खो देती है स्वाभाविक पहचान : शिव प्रताप शुक्ल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक आधुनिकता व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक पहचान और मूल स्वरूप से दूर कर देती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति, मूल्यों और स्वाभाविक विकास के साथ आगे बढ़ना ही वास्तविक आधुनिकता है। राज्यपाल राजकीय कन्या महाविद्यालय (आर.के.एम.वी.) शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

राज्यपाल ने शिक्षा और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कॉलेज की सराहना करते हुए कहा कि यह महाविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का मजबूत आधार भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की छात्राओं ने शिक्षा के साथ-साथ खेल, संस्कृति, शोध, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक जागरूकता अभियानों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि भारत आज नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति की असली शक्ति बेटियाँ हैं। जहाँ नारी का सम्मान और सशक्तिकरण बढ़ता है, वहीं राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने छात्राओं से नई तकनीकों को सीखने, नवाचार और अनुसंधान को अपनाने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने और सामाजिक मूल्यों व जिम्मेदारियों को हमेशा बनाए रखने की अपील की।

राज्यपाल ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व के कारण देश लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतवासियों को अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे।

शुक्ल ने कहा कि आर.के.एम.वी प्रदेश में युवा रेडक्रॉस का एकमात्र विधिवत पंजीकृत कॉलेज है, जो यह साबित करता है कि यह संस्था शिक्षा के साथ मानवता, सेवा, प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को भी मजबूत करती है। उन्होंने नशा निवारण के लिए कॉलेज के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि इस कॉलेज का ह्यएंटी-चिट्टा अभियानह्व हिमाचल में नशे के खिलाफ एक प्रेरक संदेश है। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नशा विरोधी नुक्कड़ नाटक की भी उन्होंने सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को एक आदर्श संस्था के रूप में विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय जनजातीय क्षेत्रों से आने वाली बेटियों के लिए भी एक सशक्त मंच बनकर उभरा है, जो समावेशी शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है और एक संतुलित व संवेदनशील समाज की नींव रखता है।

कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अनुरीता सक्सेना ने राज्यपाल का स्वागत किया और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। डीन स्टूडेंट वेल्फेयर डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

शिमला : 54 साल बाद शांत महायज्ञ शुरू, देव संस्कृति के रंग में रंगा झड़ग गांव

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश की समृद्ध और प्राचीन देव संस्कृति को फिर से जीवंत करने वाला ऐतिहासिक आयोजन शुक्रवार को जिला शिमला की जुब्बल तहसील के झड़ग गांव में शुरू हुआ। गांव में लंबे समय बाद आयोजित किया जा रहा तीन दिवसीय शांत महायज्ञ बड़ी श्रद्धा और पारंपरिक विधि-विधान के साथ आरंभ हुआ। 54 साल के अंतराल के बाद हो रहे इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महायज्ञ की शुरूआत नागेश्वर जी महाराज के मंदिर में पूजा-अर्चना और देव विधि के साथ की गई। प्रदेश और क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि और आपदाओं से मुक्ति की कामना के लिए आयोजित इस महायज्ञ में दूर-दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जब देवताओं के दल (देवलू) झड़ग गांव पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। पूरा गांव देव संस्कृति की ध्वनियों, जयघोष और लोक उत्साह से गूंज उठा। नागेश्वर देवता के कारदार और स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि 54 वर्षों बाद शांत महायज्ञ का आयोजन पूरे मान-सम्मान, परंपरा और आस्था के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देव संस्कृति और सामूहिक भागीदारी ही हिमाचल को देवभूमि की पहचान दिलाती है। हिमाचल की पुरातन संस्कृति, देवी-देवताओं में अटूट विश्वास और लोक आस्था इस प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है, और ऐसे आयोजन इसे और भी मजबूत करते हैं। गांव में तीन दिन तक धार्मिक अनुष्ठान, देव दर्शन, हवन, पारंपरिक रीति-रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। स्थानीय लोग इस महायज्ञ को शुभ और ऐतिहासिक बताते हुए पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। आयोजन को लेकर गांव में उत्सव जैसा माहौल है और हर तरफ भक्ति और सांस्कृतिक रंग देखने को मिल रहा है।

झड़ग गांव का यह आयोजन न केवल देव संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि सामुदायिक एकजुटता और लोक भावनाओं को भी मजबूत कर रहा है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल से प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल के पुत्र आनंद यशपाल की भेंट

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

प्रसिद्ध क्रांतिकारी-साहित्यकार यशपाल के सुपुत्र आनंद यशपाल, जो लंबे समय से अमेरिका में निवासरत हैं, अपने भारत दौरे के दौरान समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से मिले। इस अवसर पर दोनों ने साहित्य, इतिहास और यशपाल की साहित्यिक व क्रांतिकारी विरासत पर गहन चर्चा की।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने साहित्यकार यशपाल को याद करते हुए कहा कि वे हिन्दी साहित्य के विशिष्ट स्तम्भ, एक क्रांतिकारी युवा, समाजवादी विचारक और विस्तृत विधाओं में लेखन करने वाले लेखक थे। उन्हें साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

प्रो. धूमल ने कहा कि उनके साहित्य का वैश्विक पाठक-वर्ग तक पहुँचाना और भाषा की सीमा पार करना उनके सुपुत्र आनंद यशपाल की महत्वपूर्ण पहल रही है। आनंद ने अपने पिता के अंग्रेजी में अनूदित संस्करणों और सम्पादन कार्यों के माध्यम से यशपाल की कहानियाँ व उपन्यास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए, जिसमें ळँ२ क२ ठङ्क३ ळॅ३ ऊं्ल्ल (ऱझूठा सचऱ का अनुवाद) का प्रकाशन भी शामिल है।

आनंद यशपाल ने इस मौके पर कहा कि वे अपने पिता की याद और साहित्यिक विरासत को संजो कर रखने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहेंगे और भारत में साहित्यिक विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिये आगे भी सक्रिय रहेंगे।

सहकारिता विकास संघ चुनावों में यशवीर पाटियाल अध्यक्ष एवं सुशील सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष निर्वाचित

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

जिला हमीरपुर सहकारिता विकास संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें बिझड़ी जोन से यशवीर पाटियाल और भोरंज जोन से सुशील सिंह ठाकुर को सर्वसम्मति से क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया।

चुनाव में जिला सहकारिता विकास संघ के सभी 7 जोन के निदेशक एवं सदस्य उपस्थित रहे। सर्वसम्मति से हुए इस चयन पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा, तथा संघ के सभी निदेशकों एवं सदस्यों ने नव-निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशवीर पाटियाल ने अपने चुनाव को सभी 7 जोन के निदेशकों के विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल द्वारा सहकारिता विकास संघ के सतत विकास के लिए किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल का सहयोग हमेशा समयबद्ध, पारदर्शी और सकारात्मक रहा है। उनके प्रयासों की बदौलत सहकारिता विकास संघ ने कई बार कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदला है। जिला हमीरपुर के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में प्रो. धूमल का योगदान अविस्मरणीय है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सहकारिता विकास संघ के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी संघ को वित्तीय सहायता, बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन या किसी परियोजना के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ी, उस-उस समय अनुराग ठाकुर ने पहल करते हुए न केवल सहायता प्रदान की बल्कि संघ की कार्यप्रणाली को आधुनिक और सशक्त बनाने में भी मार्गदर्शन दिया।

जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार रेजर की धार पर काम कर रही है, फारूक अब्दुल्ला

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

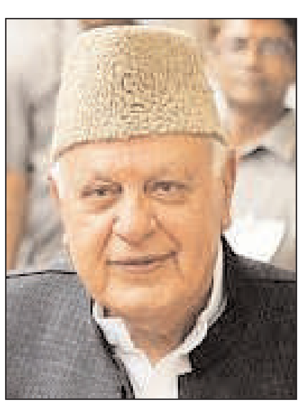

पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार रेजर की धार पर काम कर रही है क्योंकि उनके अनुसार सभी शक्तियां उपराज्यपाल में निहित हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर श्रीनगर शहर के हजरतबल इलाके में उनकी समाधि पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले वर्ष के दौरान जो कुछ भी किया जा सकता था वह हमारे सिर पर लटकी तलवार के बावजूद किया गया है। सभी शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं और हमें इन परिस्थितियों में उस्तरे की धार पर चलना होगा। जब हम राज्य का दर्जा मांगते हैं तो हम इसे अपने लिए नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इसे बहाल किया जाए ताकि राज्य का दर्जा बहाल किया जा सके। यहां लोगों को फायदा होता है।

हमारे पास चार साल और हैं। बस धैर्य रखें और देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। सभी विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों को भी अपने व्यवहार में ईमानदार होना होगा। सरकारी निर्माण कार्य में लगे स्थानीय ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका काम ईमानदार हो। अब ठेके पाने के लिए आपको ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ठेकेदारों को इंजीनियरों की पसंद पर काम मिलने के दिन अब खत्म हो गए हैं।

राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बयान में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बूढ़ों के दिन खत्म हो गए हैं। युवाओं को आगे आकर सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को समाज के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए आगे आना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और चौधरी मोहम्मद रमजान, मुबारक गुल, नजीर गुरेजी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी संस्थापक की मजार पर 'फतेहा' की नमाज अदा की।

दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती से जुड़े दिन के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में उनके पोते उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल तीर्थ में दो नए द्वारों की आधारशिला रखी। दरगाह की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर बाब-उल-सलाम और बाब-उल-नूर नाम के द्वार बनाए जा रहे हैं। एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक में प्रवेश बिंदुओं को बढ़ाना और शेख अब्दुल्ला की जयंती पर उनकी विरासत का सम्मान करना है।

घास के 350 बंडल चुराने पर एफआईआर, विरोध पर जान से मारने की धमकी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला शिमला के चौपाल उपमंडल में घास चोरी करने और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह मामला थाना चौपाल में अमर सिंह विरसांटा निवासी गांव कंडा की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी भूमि खसरा नंबर 220 से करीब 350 बंडल घास चोरी करके ले जाई गई। उन्होंने बताया कि यह घास विद्या देवी, शीला देवी, बिंदु देवी, बॉबी, लिखिल (हन्नी) और अन्य लोगों द्वारा वाहन नंबर ल्ढ6३उ-5118 में भरकर ले जाई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की और मौके पर भूमि की निशानदेही की। जांच के दौरान पाया गया कि खसरा नंबर 220 शिकायतकर्ता अमर सिंह की पत्नी के नाम दर्ज है।

पुलिस ने इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 303(2), 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस मामले में शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

संक्षिप्त-समाचार

लखनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार

कठुआ। अपराधियों के विरुद्ध जारी अभियान के क्रम में कठुआ पुलिस ने लखनपुर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लखनपुर तारिक अहमद के नेतृत्व में थाना लखनपुर की एक पुलिस टीम ने पुलिस उपनिरीक्षक यूसुफ की सहायता से अभियुक्त अख्तर हुसैन पुत्र मोहम्मद दीन निवासी बिब्रोट तहसील राजगढ़ जिला रामबन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जो लखनपुर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 55/2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के मामले में वर्ष 2024 से गिरफ्तारी से बच रहा था। उक्त आरोपी अपराध के बाद से ही गिरफ्तारी से बच रहा था। कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मामले की आगे की जाँच जारी है।

एचपी लेजर एम300 सीरीज: भारत में एसएमबी एवं जॉबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कर रहे मदद

चंडीगढ़। भारत में छोटे उद्यमों और जॉबर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके रोजाना के कामों में प्रिंटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े मेट्रो शहरों से लेकर भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों तक अपने कामों को सुगमता से करने के लिए छोटे उद्यम एवं स्थानीय प्रिंट की दुकानें तेज एवं आसानी से प्रयोग किए जा सकने वाले प्रिंटर्स पर निर्भर हैं। एचपी की लेजर एम300 सीरीज को विशेष रूप से इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें तेज प्रिंट स्पीड, ऑटो डुप्लेक्स फीचर्स, मोबाइल प्रिंटिंग एवं कम रनिंग कॉस्ट की खूबियां एक साथ मिलती हैं। स्थानीय प्रिंट की दुकानों एवं जॉबर्स को अक्सर कई तरह के फॉर्म, लीगल फाइल्स, बुकलेट्स एवं रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में तेज प्रिंटिंग एवं सतत गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। एचपी लेजर एम300 सीरीज से 30 पेज प्रति मिनट (ए4) तक की स्पीड मिलती है, 15 आईपीएम तक का डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट मिलता है और करीब 8.5 सेकेंड फर्स्ट-पेज-आउट टाइम है। सभी मॉडल्स में ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग से समय बचता है और कागज की बचत होती है। मल्टीपर्पज ट्रे से काम की व्यस्तता के बीच प्रिंटिंग का काम जल्दी पूरा होता है। एचपी एप के माध्यम से मोबाइल प्रिंटिंग से वॉक-इन कस्टमर्स और ऑफिस टीम, दोनों के लिए सीधे अपने स्मार्टफोन से ही प्रिंट करना संभव होता है। इसके टोनर की उपलब्धता भी पूरे भारत में है, जिससे बिना देरी के सुगमता से प्रिंटिंग सुनिश्चित होती है।

रोटरी क्लब पंचकूला ग्रीन्स ने द राइजिंग गुरुकुल में इंटरैक्ट क्लब का शुभारंभ किया

चंडीगढ़। रोटरी क्लब पंचकूला ग्रीन्स ने दि राइजिंग गुरुकुल स्कूल, जिला पंचकूला के इंटरैक्ट क्लब के स्थापना समारोह का सफल आयोजन किया। यह पहल युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में एजी रोटेरियन डॉ. मुकेश अग्रवाल द्वारा संचालित योग सत्र तथा राष्ट्रीय योग खिलाड़ी हरशीन कौर का सम्मान विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। क्लब ने रोटेरियन दीपक गुप्ता, रोटेरियन पुनीत गोयल, रोटेरियन देशराज ठकराल, प्रिंसिपल निधि खिरबत और डायरेक्टर प्रदीप खिरबत को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद प्रकट किया। रोटरी क्लब और द राइजिंग गुरुकुल मैनेजमेंट ने प्रेसिडेंट रोटेरियन विनीत गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी की सराहना की, जिनके प्रयासों ने इस आयोजन को प्रभावशाली और यादगार बनाया।

राणा सहित अन्यों ने शेर-ए-कश्मीर के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने शुक्रवार को शेर-ए-कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 120वीं जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राणा ने जेकेएनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, विधानसभा अध्यक्ष ए.आर. राठौर, सांसद रमजान चैधरी, मंत्री जावेद अहमद डार और विधायकों के साथ शेख अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में मंत्री ने शेख अब्दुल्ला को एक प्रखर राजनेता और परिवर्तनकारी नेता बताया जिनके योगदान ने जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने पर अमिट छाप छोड़ी है। शेख अब्दुल्ला के दूरगामी सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में शुरू किए गए क्रांतिकारी भूमि सुधारों ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया। इन सुधारों ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया तथा हाशिये पर पड़े और वंचित समुदायों के बड़े हिस्से को सशक्त बनाया, जो लंबे समय से समाज के हाशिये पर रह रहे थे। राणा ने इस बात पर जोर दिया कि इन उपायों ने न केवल आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया, बल्कि आम लोगों के लिए अधिक सम्मान, भागीदारी और अवसर का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने आगे कहा कि न्याय, समानता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों के प्रति शेख अब्दुल्ला की अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मौसम

कन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान -0.2 दर्ज हुआ

सुंदरनगर-सोलन में मनाली से भी ज्यादा ठंड, मैदानी इलाके शिमला-कुफरी से सर्द

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में दिसंबर की शुरूआत से ही प्रचंड सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह है कि मैदानी तथा मध्यपर्वतीय इलाके भी अब पहाड़ों से ज्यादा ठंडे हो गए हैं। शुक्रवार सुबह सुंदरनगर और सोलन का पारा मनाली से भी नीचे दर्ज किया गया, जबकि कई मैदानी शहर शिमला और कुफरी से अधिक ठंडे रहे। एक दर्जन शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। इससे प्रदेश में सर्दी का असर बेहद तीखा हो गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम पाया गया है।

सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री, सोलन में 2.1 डिग्री और मनाली में 3.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री और पर्यटन स्थल कुफरी का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

इसी तरह भुंतर 2.5, धर्मशाला 6.8, ऊना 5.5, नाहन 9, पालमपुर 4.5, कांगड़ा 5.6, मंडी 3.7, बिलासपुर 7.0, हमीरपुर 3.8, जुब्बड़हट्टी 7.6, नारकंडा 4.0, रिकांगपिओ 2.2 और सराहन में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज हुआ। लाहौल-स्पीति में पारा शून्य से नीचे बना हुआ है और दो शहरों में तापमान माइनस में दर्ज किया गया। ताबो आज सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान -8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कुकुमसेरी में पारा -5.2 डिग्री तक लुढ़क गया। जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा में भी तापमान -0.2 दर्ज हुआ।

कड़ाके की ठंड के बीच जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलस्त्रोत जम गए हैं और स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति में कई नालों व झरनों का पानी बर्फ में तबदील हो गया है।

उधर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। बिलासपुर में शुक्रवार सुबह घने कोहरे से दृश्यता मात्र 100 मीटर तक सीमित हो गई, जबकि मंडी में दृश्यता 500 मीटर दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले दो दिन मैदानी जिलों के कुछ स्थानों पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य में धूप खिली रहेगी, लेकिन उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कल यानी 6 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। 7 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों में मौसम के बिगड़ने का अनुमान है, जिसके चलते मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, हालांकि मैदानों में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को मौसम सामान्य और साफ रहने की संभावना जताई गई है।

इस बार दिसंबर में बारिश और बर्फबारी के अभाव ने सर्दी को और तेज बना दिया है। प्रदेश में एक माह से बादल नहीं बरसे हैं, जिससे खेतों में नमी कम हो गई है और किसान फसलों की बिजाई में परेशानी का सामना कर रहे हैं। गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

सीएम ने पारदर्शी टेंडरिंग प्रणाली और ग्रामीण विकास कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश

टेंडर से संबंधित जानकारी सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध करवाई जाए: नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभागीय कामकाज को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित किसी भी विभाग का यदि टेंडर एचईडब्ल्यू पोर्टल पर जारी होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की सही, समयबद्ध और सटीक जानकारी मिल सके। इससे निगरानी और क्रियान्वयन की गुणवत्ता और बेहतर होगी।

इस पोर्टल के माध्यम से जनता को भी टेंडर्स की जानकारी मिलेगी, जिससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वीरवार को देर शाम सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित विकास एवं पंचायत विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और मजबूत करने के लिए निर्धारित सभी योजनाओं को समय से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जिन पंचायतों की आबादी 1000 से अधिक है, उन गावों की कच्ची फिरनियों को पक्का करना है, ताकि लोगों को आवागमन सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 639 फिरनियों को पक्का किया जा चुका है, जबकि 303 कार्य प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें बैठक एवं अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में ह्यमहिला चौपालह्न का निर्माण करवा रही है। पहले चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 480 महिला चौपालों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 274 चौपालों का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण के तहत 994 ई-पुस्तकालयों का नवीनीकरण और फर्नीचर लगाया जा चुका है। इन पुस्तकालयों में जल्द ही पुस्तकें व कंप्यूटर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 415 इनडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं।

इसी तरह से विभिन्न अनुसूचित जातियों के लिए हर जिले में सामुदायिक हॉल के निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। अब तक 366 पंचायतों में से 202 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 140 हॉल का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद साइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री अनीश यादव, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री राहुल नरवाल, मुख्मंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा व श्री राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने पांच लेबर कोर्टों की स्थापना और ईएसआई अस्पतालों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों के श्रम संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्ट शीघ्र स्थापित किए जाएं। इन कोर्टों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कार्य को संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता के साथ पूरा करें। मुख्यमंत्री वीरवार देर शाम सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लेबर कोर्टों की स्थापना से लाखों श्रमिकों को समयबद्ध न्याय मिलेगा और औद्योगिक वातावरण में पारदर्शिता एवं विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों अस्पतालों के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के नागरिकों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बावल में बन रहे ईएसआई अस्पताल का निर्माण कार्य 86 प्रतिशत, पंचकूला में 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ में 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है ।बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक 250 कैंटीन स्थापित की जाएगी, जहां पर श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण राज्य सर कार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चाहे विवादों का त्वरित निपटान हो या स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, राज्य सरकार हर क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल श्रम विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभागीय समन्वय और तेज गति से कार्य होने पर निर्धारित समय के भीतर सभी लक्ष्य पूरे होंगे और श्रमिकों को लाभ मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद साइन, श्रम विभाग के आयुक्त श्री डीके बेहरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

सांसद खेल महोत्सव के दूसरे चरण में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिताएं हुई सम्पन्न

लाडवा। सांसद नवीन जिन्दल के मार्गदर्शन में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दूसरे चरण के तहत आज गांव धनौरा जट्टान, लाडवा स्थित राजीव गांधी खेल। स्टेडियम में विधानसभा स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेते हुए अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फिटनेस का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। दर्शकों ने खिलाड़ियों के बीच हुए कड़े मुकाबलों को खूब सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सुरेंद्र सिंगला, वाइस चेयरमैन मार्किट कमेटी लाडवा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सांसद नवीन जिन्दल द्वारा युवाओं को खेलों से जोड़ने का यह निरंतर प्रयास अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक विकास में सहायक हैं बल्कि उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम भी हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएँ दीं। प्रतियोगिता के परिणामों में खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। 60 किलोग्राम वर्ग में विकास ने प्रथम स्थान और दीपक ने द्वितीय स्थान हासिल किया। 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक प्रथम और पारस द्वितीय स्थान पर रहे। 80 किलोग्राम वर्ग में पवन ने प्रथम स्थान जबकि वंश द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं 85 प्लस किलोग्राम वर्ग में साहिल ने प्रथम और दिवांश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। सांसद खेल महोत्सव की इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सुभाष सिंह, सरपंच धनौरा जट्टान, गुरनाम सैनी, भाजपा नेता अंकुश गोयल, सत्य प्रकाश, राकेश गर्ग, सुरेंद्र गर्ग, विक्रम डूडा, विक्की मेहरा, प्रदीप कुमार सरपंच निवारसी, सतीश कुमार, जय सिंह शर्मा, सलिंद्र कुमार लाडवा हल्का प्रभारी, राजू कुमार सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों का विशेष सहयोग रहा।

सेवा में देरी पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के खिलाफ राइट टू सर्विस आयोग का बड़ा निर्णय

चंडीगढ़। हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित स्टाम्प शुल्क वापसी तथा सुरक्षा ऑडिट योजना के दो मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बावजूद सेवाओं का समयबद्ध निपटारा नहीं किया गया। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्टाम्प शुल्क वापसी मामले में अपील स्वीकार होने के बाद प्रकरण पूरी तरह राइट टू सर्विस अधिनियम के दायरे में आता है। आयोग ने विभाग द्वारा दी गई दलील को अस्वीकार करते हुए निर्देश दिया था कि विभाग प्रमुख आयोग द्वारा 08 अगस्त 2025 को दिए गए अवलोकनों का विस्तृत उत्तर प्रेषित करें। सुरक्षा ऑडिट योजना मामले में यह तथ्य सामने आया कि फाइल कई स्तरों पर अनावश्यक रूप से लंबित रखी गई। विशेष रूप से, जिला सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम केंद्र, फरीदाबाद में तैनात उद्योग विस्तार अधिकारी के पास प्रकरण अत्यधिक अवधि तक लंबित पाया गया। आयोग ने विलम्ब के कारणों को असंतोषजनक मानते हुए राइट टू सर्विस अधिनियम की धारा 17(1)(") के तहत पांच हजार रुपये का दंड लगाने का आदेश दिया है। विभाग प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि यह राशि दिसंबर 2025 के वेतन से काटकर जनवरी 2026 में राज्य कोष में जमा कराई जाए। अन्य अधिकारियों से प्राप्त जवाबों को देखते हुए उनके विरुद्ध नोटिस वापस ले लिए गए हैं, परंतु आयोग ने सभी को चेतावनी दी है कि भविष्य में सेवाओं की अधिसूचित समय सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि नोटिस जारी होने के बाद विभाग ने शिकायतकर्ता के दोनों मामलों में कार्यवाही पूरी कर दी है।

रोटरी क्लब ने सरकारी स्कूल के 35 बच्चों को बांटे स्कूल बैग

लाडवा। शुक्रवार को शहर की रोटरी क्लब लाडवा द्वारा निवारसी कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला के 35 बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। बाल वाटिका से लेकर पाँचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ये बैग प्रदान किए गए। रोटरी क्लब के प्रधान संजीव जिंदल ने बताया कि क्लब समय-समय पर जरूरतमंद बच्चों की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक कार्य करता रहता है। इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों को बैग देकर उनकी शिक्षा में सहयोग करने का प्रयास किया गया है। क्लब पदाधिकारियों ने स्कूल के अध्यापकों को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होने पर रोटरी क्लब द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार ने रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत सराहनीय है और इससे बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर विकास सिंघल, राकेश खुराना, दुर्गेश गोयल, रणजीत सिंह, रवि गिरधर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पवन गर्ग ने नायब सैनी की घोषणाओं पर जताया आभार

सिटी दर्पण संवाददाता
लाडवा

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाडवा व बाबैन क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण विकास घोषणाओं को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। वरिष्ठ भाजपा नेता पवन गर्ग ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होंगे और स्थानीय जनता को सीधे तौर पर बड़ा लाभ मिलेगा। पवन गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित योजनाओं के लागू होने से लाडवा-बाबैन क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार आएगा और ग्रामीण विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों को देखते हुए यह घोषणाएं बेहद आवश्यक थी।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लाडवा क्षेत्र के गांव धनौरा में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज क्षेत्र का एकमात्र कॉलेज है। शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रखते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पहले भी इस कॉलेज के विकास के लिए 21 लाख रुपये की अनुदान राशि दे चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने खेत-खलिहान योजना के तहत 25 किलोमीटर ग्रामीण रास्तों के निर्माण व विकास की भी घोषणा की है।

करनाल में 162 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है यूनिटी मॉल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के करनाल में बनने जा रहा यूनिटी मॉल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) उत्पादों, विशेषकर ह्यवन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टह्न पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच का काम करेगा। शहर की औद्योगिक सम्पदा के सेक्टर-37 में ग्रांड ट्रंक रोड के साथ 162.88 करोड़ रुपये की लागत से 3.87 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस मॉल को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां, करनाल में निमार्णाधीन यूनिटी मॉल परियोजना तथा फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनाए जा रहे दो वर्किंग वूमेन हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि परियोजना का खुदाई कार्य तीव्र गति से जारी है, जो निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्माण की स्वीकृत समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने तथा कार्य की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए। यह परियोजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से विकसित की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित इस परियोजना स्थल से दिल्ली और चंडीगढ़ समेत अन्य प्रमुख उत्तरी शहरों से भी बेहतरीन कनैक्टिविटी है। करनाल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र के तौर पर उभरने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति से इस परियोजना के व्यापक आर्थिक प्रभाव को और मजबूती मिलेगी।

इस यूनिटी मॉल को देशभर के एमएसएमई उत्पादों-विशेषकर ह्यवन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टह्न श्रेणी के उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमियों की मार्केटिंग लागत कम होगी, घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में उनकी पहचान बढ़ेगी और नए व्यावसायिक सहयोग के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य दहिया ने बताया कि यह यूनिटी मॉल राज्य के विशिष्ट उत्पादों के स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, बिजनेस-टू-बिजनेस नेटवर्किंग हब तथा पर्यटन आकर्षण के रूप में भी कार्य करेगा, जो देश की विविध विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। यह परियोजना केंद्र सरकार के स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने, बाजार पहुंच बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले अवसंरचना तंत्र के माध्यम से अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति से पूरी तरह मेल खाती है। रस्तोगी ने एचएसआईआईडीसी और एमएसएमई निदेशालय को सुचारू एवं प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रारम्भिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने और परियोजना की गति बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

नायब सिंह सैनी का लाडवा को बड़े प्रोजेक्टों की सौगात दिए जाने पर विधानसभा के पदाधिकारियों ने जताया आभार

सिटी दर्पण संवाददाता
लाडवा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा लाडवा के लिए विकास की घोषणाएं किए जाने पर विधानसभा के पदाधिकारियों ने आभार व धन्यवाद जताया। इन घोषणाओं से लाडवा विधानसभा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मजबूत होगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनाज मंडी लाडवा में आयोजित संत शिरोमणि सैन जी महाराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की हैं। लाडवा को बड़े प्रोजेक्ट मिलने पर विधानसभा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मार्केट कमेटी चेयरमैन डा. गणेश दत्त, नगर पालिका चेयरपर्सन साक्षी खुराना, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र दबखेड़ा शामिल रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के विकास कार्यों को गति देने के लिए 16.50 करोड़ रुपए की लागत के 6 प्रोजेक्टों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें गांव सिरसमा और गांव बजीदपुर में नलकूल व पेयजल पाईप लाईन, गांव गजलान में पेयजल पाईप लाईन, करनाल-रम्बा-इन्द्री-लाडवा-शाहबाद सडक के विधानसभा लाडवा क्षेत्र के अधीन आने वाले सडक का सुद्दढ़ीकरण और अनाजमंडी बाबैन की विशेष मुरम्मत कार्य का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा गांव किशनपुरा में पेयजल पाईप लाईन का शिलान्यास शामिल है।

इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष अंकुश गोयल, मार्केट कमेटी सदस्य ज्ञान सिंह, पूनम सैनी, सन्नी कालडा, संजीव, निशा गोयल, कर्मबीर, देवेंद्र गोल्डी, विजय वधावन सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विदेशी प्रतिनिधियों से नेता प्रतिपक्ष की भेंट परंपरा को दरकिनार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की यात्रा पर आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष से औपचारिक भेंट सुनिश्चित की जाती है। यह परंपरा केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत के सशक्त, संतुलित और सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक रही है लेकिन विदेशी प्रतिनिधियों से नेता प्रतिपक्ष की भेंट परंपरा को दरकिनार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है। मीडिया को जारी बयान सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह हों या भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी सभी ने इस परंपरा का आदर करते हुए विपक्ष की भूमिका को महत्व दिया। संसद की गरिमा इसी समावेशी दृष्टिकोण से मजबूत होती आई है। दुर्भाग्य से वर्तमान भाजपा सरकार ने इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया है। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न करना न केवल संसदीय मयार्दा का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों के सम्मान और सहभागिता से चलता है। भाजपा सरकार द्वारा स्थापित परंपराओं को नजर अंदाज करना देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों के लिए हानिकारक है। सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह लोकतांत्रिक मान्यताओं का सम्मान करे, संसदीय मयार्दाओं का पुनः पालन सुनिश्चित करे और विपक्ष को उसकी संवैधानिक भूमिका निभाने का समुचित अवसर दे।

सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में पेयजल की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र सिरसा सहित पूरे हरियाणा के कई गांव आज भी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो करती है, लेकिन जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं देता। सांसद ने कहा कि सिरसा जिला के रानियां क्षेत्र में 40 से अधिक ऐसे गांव है जहां पर नहरी पानी का कोई प्रबंध नहीं है तो राजस्थान सीमा से सटे ऐलनाबाद क्षेत्र के गांवों में आज भी लोग खरीदकर पानी पी रहे हैं।

शिल्पकला और लोक संस्कृति के अनोखे झरोखों के साथ महोत्सव का हुआ समापन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

> **अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2025 की गूंज पहुंची विश्व के कोने-कोने तक अदभुत और अनोखी शिल्पकला के साथ देश-प्रदेश की लोक संस्कृति ने ब्रह्मसरोवर के तटों को दी नई पहचान**

कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के पावन तट 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज विश्व के कोने-कोने तक पहुंची। इस गूंज के साथ ही महोत्सव ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है।

इस महोत्सव में अद्भुत शिल्पकला के साथ-साथ देश-प्रदेश की लोक संस्कृति ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज विदेशों में भी सुनाई दी, यहां पर आने वाला प्रत्येक पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गाथा को भुला नहीं पा रहा है और इन अनोखे पलों को दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ लाखों श्रद्धालु अपने कैमरों में कैद कर रहे है। इस महोत्सव की अनोखी छटा अपने आप में लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां एक ओर शिल्पकारों की अद्भुत और आश्चर्य चकित करने वाली शिल्पकला ने लोगों को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर किया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों की अलग-अलग वेशभूषा की लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया है और इस भव्य आयोजन के लिए लोग सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते नजर आए।

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर आने वाले पर्यटकों ने इस महोत्सव की हर क्षणों का लुफ्त उठाया।

कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए एनरोलमेंट की तिथियां निर्धारित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क के साथ 08 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात 300 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 21 दिसंबर से 28 दिसम्बर तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 29 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रों के विवरणों में 06 जनवरी से 08 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न/शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन भरी जानी है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी विद्यार्थी का आवेदन फार्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अन्तिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। बोर्ड प्रवक्ता ने आगे बताया कि कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुमार्ना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमित/मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थी का विद्यालयों द्वारा पुनः रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100/-रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है उनके एनरोलमेंट फॉर्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपए प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा। उन्होंने स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न भरते समय विद्यार्थी के आधार नम्बर के साथ-साथ पिता का आधार नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि किसी कारणवश पिता का आधार नंबर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। इस बार एनरोलमेंट रिटर्न के दौरान परीक्षार्थियों की अढअफ क्ळ का कॉलम भी दिया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों की अढअफक्ळ संख्या दर्ज की जानी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जो फोटो आवेदन-पत्र में भेजे जाने हैं, वह विद्यालय की वर्दी में ही हों, जिससे यह अलग पहचान हो सके कि अमुक परीक्षार्थी अमुक विद्यालय का है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट ऑनलाइन पार्टल पर आवेदन फार्म भरते समय अन्य राज्य से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिहस्ताक्षरित एसएलसी/टीसी एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 10वीं का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरान्त उनमें केवल दो त्रुटियों (जन्म तिथि को छोडकर) को बिना शुल्क तथा दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300 रुपए प्रति शुद्धि शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि विद्यालय अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना सुनिश्चित करें। विद्यालय एनरोलमेंट के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को ना भेजें। ऑनलाइन रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पलाइन दूरभाष नम्बर 01664-254300, 254302, एवं दूरभाष नम्बर 01664-244171 से 176 ए७३.164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल पर मेल भेजी जा सकती हैं।

संपादकीय

भारत-रूस मेगा डील: पुतिन-मोदी मुलाकात से खुलेंगे विकास और सुरक्षा के नए दरवाजे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई ऐतिहासिक बैठक ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा दी है। रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के 25 वर्ष पूरे होने के विशेष अवसर पर हुई यह यात्रा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वैश्विक परिवर्तित परिदृश्य में एक मजबूत और बहुआयामी सहयोग की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत और रूस के बीच उन क्षेत्रों में साझेदारी को सुदृढ़ किया है, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमताओं को निर्णायक रूप से प्रभावित करेंगे। बैठक के दौरान अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका केंद्र बिंदु श्रम, स्वास्थ्य, समुद्री परिवहन, शिक्षा, विज्ञान, मीडिया, खाद्य सुरक्षा, सीमा शुल्क प्रबंधन और रक्षा अनुसंधान जैसे व्यापक क्षेत्र रहे। दोनों देशों ने अस्थायी श्रमिक गतिविधि को विनियमित करने पर सहमति जताई, जिससे भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए रूस में रोजगार अवसर बढ़ेंगे। यह कदम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की बढ़ती कार्यबल क्षमता को नई दिशा प्रदान करेगा। साथ ही, अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का निर्णय दोतरफा सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ समझौता चिकित्सा शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग को नई उंचाई देगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न केवल साझा शोध बल्कि नीतिगत सहयोग को भी बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार किया। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े समझौते भारतीय बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होंगे। ऐसे समय में जब वैश्विक सप्लाई चेन लगातार दबाव में है, यह साझेदारी खाद्य मानकों को लेकर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। समुद्री क्षेत्र में हुए समझौते भी उल्लेखनीय हैं। ध्रुवीय जलक्षेत्र में जहाज परिचालन के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण से लेकर समुद्री बोर्डों के बीच सहयोग तक, इन समझौतों का लक्ष्य भारत की समुद्री क्षमताओं को उन्नत करना है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की विशेषज्ञता और भारत की उभरती समुद्री महत्वाकांक्षाओं का यह मेल भविष्य के नौवहन एवं व्यापार मार्गों को नया आयाम देगा। कृषि और उर्वरक क्षेत्र में भी सहयोग को गहराई मिली है। यूरालकेम और भारतीय उर्वरक कंपनियों के बीच हुए एमओयू आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और घरेलू कृषि उत्पादन को समर्थन देंगे। इससे कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से तब जब वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतें और उपलब्धता लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही हैं। सीमा शुल्क प्रबंधन और माल-वाहन संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से 'आगमन-पूर्व सूचना आदान-प्रदान' के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। इससे व्यापार को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पोस्टल क्षेत्र में भारतीय डाक और रूसी पोस्ट के बीच हुए समझौते ई-कॉमर्स और पार्सल लॉजिस्टिक्स में बड़े बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित सहयोग समझौतों ने द्विपक्षीय संबंधों को बौद्धिक आधार भी दिया है। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे और रूस की टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग नई पीढ़ी की तकनीकी साझेदारी को मजबूती देगा। वहीं मुंबई विश्वविद्यालय और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच अकादमिक सहयोग दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर खोलता है। मीडिया क्षेत्र में प्रसार भारती और विभिन्न रूसी मीडिया समूहों के बीच हुए समझौते सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम हैं। इससे दोनों देशों के बीच सूचना आदान-प्रदान, कंटेंट निर्माण और प्रसारण क्षमता को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर पुतिन-मोदी बैठक से हुए ये व्यापक समझौते स्पष्ट करते हैं कि भारत और रूस की मित्रता केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और व्यवहारिक साझेदारी है, जो बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच दोनों देशों को आर्थिक स्थिरता, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक सुरक्षा और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के ठोस अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा ने यह साबित किया है कि भारत और रूस की दोस्ती भविष्य की बड़ी चुनौतियों और अवसरों के बीच एक सशक्त धुरी की तरह उभर सकती है।

राजभवन बनाम लोकभवन की संस्कृति

मृत्युंजय दीक्षित (हि.स)

केंद्र सरकार ने भारत के सभी राजभवनों को लोकभवन कहे जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई अवसरों पर गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संदेश दे चुके हैं, स्वाभाविक है इससे गहन रूप से घर कर गई वैचारिक गुलामी की मानसिकता भी धीरे- धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रीराम जन्मभूमि पर नव निर्मित दिव्य-भव्य मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आगामी 10वर्षों तक गुलामी की मानसिकता को समाप्त रकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

इसी श्रृंखला में देश में शासन के प्रतीकों में शांत कितु गहन व व्यापक प्रभाव डालने वाले परिवर्तन किए जा रहे हैं। सनातन हिंदू सभ्यता में नामों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि व्यक्ति का जैसा नाम होगा उसका प्रभाव व व्यक्तित्व भी उसी प्रकार होगा। उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि लिए राजभवनों को अब लोकभवन नाम दिया गया है। राजभवन का नामकरण लोकभवन करने का तात्पर्य है उसे लोकहितकारी बनाना। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह भी है कि इन भवनों में निवास करने वालों को स्मरण रहे कि उनका काम शक्ति प्रदर्शन नहीं अपितु जनसेवा है।

मोदी सरकार ने इसके पूर्व भी कई स्थानों के नाम बदले हैं जैसे राजपथ अब कर्तव्यपथ है। राजपथ का अर्थ है 'राजा का मार्ग' जो शक्ति का प्रतीक है, वहीं कर्तव्य पथ, कर्तव्य का स्मरण कराता है। वर्ष 2016 में रेस कोर्स का नाम परिवर्तित करके इसको लोक कल्याण मार्ग किया गया। अब प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। यह नाम बताता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा और समर्पण की भावना का केंद्र है न कि मात्र प्रशासनिक केंद्र। इसी प्रकार केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदला गया है और उसे अब कर्तव्य भवन कहा जाता है।

नाम परिवर्तन का उद्देश्य है विचारों में परिवर्तन लाना। सभी सरकारी संस्थाएं अब सेवा और कर्तव्य की भाषा बोल रही हैं। गुजरात लोकभवन ने सोशल मीडिया में अपने चित्र साझा करते हुए लिखा है, ' यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं अपितु जनसेवा की भावना को और गहराई से आत्मसात करने का संकल्प है।' अब यह भवन केवल राज्यपाल का निवास नहीं नागरिकों, विद्यार्थियों , किसानों, शोधकताओं तथा सामाजिक संगठनों का भवन है।

कई राज्यों के राज्यपालों ने राजभवन का नामकरण लोकभवन करने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को दी है। एक समय था जब राजभवनों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किया जाता था। नेहरू काल से लेकर वर्ष 2014 के पूर्व तक 94 बार राज्यपालों की शक्तियों का दुररुपयोग करके राज्य सरकारें गिराई गयीं और राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

यद्यपि अब समय बदल रहा है, राजभवन लोक भवन बन रहे हैं तथापि पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में घोर भाजपा विरोधी सरकार हैं जिनका अपने राज्यपालों के साथ विवाद चलता रहता है। अभी हाल ही में इन राज्यों में राज्यपालों के साथ लंबित विधेयकों का प्रकरण उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया था।

वर्ष 2014 के पूर्व तक राजभवनों मे निवास करने वाले राज्यपाल की पहुंच जनता तक नहीं होती थी किंतु अब यह संभव हो गया है। बंगाल के हालात बहुत दयनीय हैं और कई बार वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई हैं, केरल और तमिलनाडु की स्थिति भी अच्छी नहीं है किंतु राज्यपालों ने अत्यंत संयमित रूप से कार्य किया है। राज्यपालों ने जनता के मध्य जाकर परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

'नाम में क्या रखा है', कहने वाले लोग इस प्रयास का उपहास कर सकते हैं। राजभवन बनाम लोक भवन पर व्यापक वाद-विवाद भी हो सकता है किंतु जो परिवर्तन लोक भवन बने राजभवन में दिख रहे हैं उसकी प्रशंसा तो करनी ही होगी।

श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष से लेकर राष्ट्र निर्माण हेतु अभूतपूर्व योगदान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

आज, हम एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी और आधुनिक मानव समाज की दिशा निर्धारित करने वाले प्रगतिशील उपायों के पुरोधा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, समाज सुधारक और इन सबसे अधिक एक राष्ट्र-निमार्ता के रूप में उनके अथक प्रयासों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने केवल भारत के संविधान का मसौदा ही तैयार नहीं किया बल्कि एक ऐसे समावेशी और सशक्त राष्ट्र का खाका भी प्रस्तुत किया जहां प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। इन मूलभूत मूल्यों से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने जन कल्याण और सुशासन को बढ़ावा देने वाली कई पहलें की हैं।

27 नवंबर, 2025 को पेरिस स्थित यूनेस्को (UNESCO) मुख्यालय में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण विश्व डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण का साक्षी बना। विश्व के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष यह प्रतिमा न केवल भारत के एक नेता के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बल्कि न्याय के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में खड़ी है। पट्टिका पर 'भारत के संविधान का शिल्पकार' लिखा है, फिर भी ये शब्द उस व्यक्ति की विरासत का पूरी तरह से उल्लेख नहीं कर सकते, जिसने न केवल भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को समग्रतः आकार देने में मदद की।

अपने पूरे जीवनकाल में, बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के अधिकार और उनके कल्याण की वकालत करते हुए न्याय के लिए संघर्ष किया। गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference) में दलित वर्गों (Depressed Classes) के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जीवन निर्वाह मजदूरी, काम करने की उचित स्थिति, दमनकारी जमींदारों से किसानों की मुक्ति और दबे-कुचले लोगों को प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की पुरजोर वकालत की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों और दलितों की पीड़ा को देखा था। बंबई में, वह बंबई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक कमरे वाली चॉल (tenements) में मिल मजदूरों के साथ 10 साल से अधिक समय तक रहे, जहाँ कोई आधुनिक सुविधाएँ नहीं थीं और प्रत्येक मंजिल पर सभी उद्देश्यों के लिए केवल एक शौचालय और एक नल था। इन परिस्थितियों ने उन्हें श्रमिकों के जीवन को काफी नजदीक से समझने का अवसर दिया। उन्होंने आम जनता को एकजुट किया और 1936 में भूमिहीन लोगों, गरीब काश्तकारों, कृषकों और श्रमिकों के कल्याण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना की। 17 सितंबर, 1937 को बंबई विधानसभा के पुणे सत्र के दौरान, उन्होंने कोंकण में 'खोती' भूमि कार्यकाल प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। 1938 में, उन्होंने बंबई में काउंसिल हॉल तक किसानों के मार्च का नेतृत्व किया और किसानों, श्रमिकों और भूमिहीनों के लोकप्रिय नेता बन गए। वह कृषि काश्तकारों की दासता (बंधुआ मजदूरी) को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश करने वाले पहले भारतीय विधायक थे। उन्होंने औद्योगिक विवाद विधेयक (Industrial Disputes Bill), 1937 का भी कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार में कटौती की गई थी।

अर्जुन राम मेघवाल

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था के दौर में डॉ. अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में भारत में मजदूरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार होने और उद्योगों का विस्तार होने पर उद्यमियों को समृद्धि के अवसर मिले, लेकिन श्रमिकों को उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया। उस समय डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण उपाय पेश किए, जिससे सरकार की श्रम नीति की नींव पड़ी। उन्होंने श्रमिकों से जुड़े जटिल मुद्दों का बहुत दक्षता के साथ समाधान निकाला जिससे उन्हें कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों से सम्मान प्राप्त हुआ।

वर्ष 1943 में बंबई से आकाशवाणी से किए गए अपने संबोधन में डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित 'जीवन की उचित स्थिति' सुरक्षित करने का आग्रह किया। उनके प्रयासों से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिली। उन्होंने प्रमुख श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण हेतु अहम योगदान किया जिसमें युद्ध चोट (मुआवजा बीमा) विधेयक, असुरक्षित निरीक्षणों के कारण मिलों में होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने से संबंधित बॉयलर (संशोधन) विधेयक 1943, भारतीय खान और ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक, खनिक मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, कोयला खान सुरक्षा (स्टोविंग) संशोधन विधेयक और कामगार मुआवजा संशोधन विधेयक शामिल हैं।

9 दिसंबर 1943 को, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने धनबाद कोयला खदानों का दौरा किया और खदानों के संचालन व श्रम स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए जमीन से 400 फीट नीचे गए। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1944 का कोयला खान श्रम कल्याण अध्यादेश (Coal Mine Labour Welfare Ordinance) आया, जिससे श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कोष बनाया गया। उन्होंने कोयले की खानों से निकाले गए कोयले पर कर को दोगुना करके इस कोष को मजबूत किया, जिससे खनिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हुए। 8 नवंबर 1943 को, उन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक भी पेश किया, जिसमें नियोक्ताओं के लिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया।

8 फरवरी 1944 को कोयला खदानों में महिलाओं के जमीन के भीतर काम पर से प्रतिबंध हटाने के विषय पर विधानसभा में बहस के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि किसी भी उद्योग में लैंगिक आधार पर भेदभाव के बिना समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्थापित किया गया है।' यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। माइन्स मैटरनिटी बेनिफिट (संशोधन) बिल 1943 के माध्यम से उन्होंने मातृत्व लाभ को मजबूत किया और उन्हें अनुपस्थिति के कारण आर्थिक दंड से बचाने का प्रावधान किया। वर्ष 1945 में उन्होंने अधिनियम में और संशोधन किए ताकि महिलाओं को प्रसव से दस सप्ताह पहले जमीन के भीतर कार्य करने से बचाया सके और उनके लिए प्रसव से दस सप्ताह पहले और चार सप्ताह बाद कुल मिलाकर चौदह सप्ताह का मातृत्व अवकाश सुनिश्चित किया जा सके।

26 नवंबर 1945 को नई दिल्ली में भारतीय श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने श्रमिकों के प्रति सरकार के दायित्वों की समीक्षा की और श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रम कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रगतिशील श्रम कल्याण कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने कहाः–

' कोई यह कह सकता है कि अंग्रेजों को श्रम कानून की एक उचित संहिता बनाने में 100 साल लग गए, किंतु यह कोई तर्क नहीं है कि हमें भी भारत में 100 साल लगने चाहिए। इतिहास का अध्ययन केवल इस दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए कि दूसरे देशों की गलतियों की नकल कितनी अच्छी तरह की जाए। हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि यह जान सकें कि लोगों ने क्या गलतियां की है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इतिहास हमेशा एक उदाहरण नहीं होता। अक्सर यह एक चेतावनी होता है।'

अगले दिन उसी सम्मेलन में, उन्होंने कारखानों में काम के घंटे घटाकर 48 घंटे प्रति सप्ताह करने, वैधानिक औद्योगिक कैंटीन शुरू करने और कामगार मुआवजा अधिनियम, 1934 में संशोधन करने के लिए कानून प्रस्तावित किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन के लिए कानूनों का मसौदा तैयार करने की योजना भी घोषित की। 21 फरवरी 1946 को, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने साप्ताहिक काम के घंटों को घटाकर 48 करने, ओवरटाइम दरों को तय करने और सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए कारखाना (संशोधन) विधेयक पेश किया। प्रवर समिति (select committee) द्वारा समीक्षा के बाद, अंबेडकर द्वारा समर्थित यह ऐतिहासिक कानून 4 अप्रैल 1946 को पारित किया गया था।

अभ्रक खनन उद्योग में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए एक कोष बनाने के लिए उनके द्वारा पेश किया गया अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष विधेयक (Mica Mines Labour Welfare Fund Bill), 15 अप्रैल 1946 को पारित किया गया था। इसने बाल और महिला मजदूरों के लिए सुविधाओं और काम करने की स्थितियों में सुधार किया, जिसमें काम के घंटे और मजदूरी के मुद्दे शामिल थे। डॉ. अंबेडकर ने 11 अप्रैल 1946 को न्यूनतम वेतन विधेयक (Minimum Wages Bill) भी पेश किया, जिसमें समान नियोक्ता-श्रम प्रतिनिधित्व वाली सलाहकार समितियों और बोर्डों का प्रस्ताव था। बाद में 9 फरवरी 1948 को इसे कानून का रूप दिया गया।

डॉ. अंबेडकर ने कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले श्रमिक आंदोलन का विरोध किया, उन्होंने उत्पादन के सभी साधनों को नियंत्रित करने के मार्क्स के सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण (totalitarian approch) को खारिज कर दिया। वह मार्क्स के इस विचार से असहमत थे कि निजी संपत्ति को खत्म करने से गरीबी और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अपने निबंध 'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' में, वह लिखते हैंः–

'क्या कम्युनिस्ट यह कह सकते हैं कि अपने मूल्यवान उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्होंने अन्य मूल्यवान उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया है? उन्होंने निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया है। यह मानते हुए कि यह एक मूल्यवान उद्देश्य है, क्या कम्युनिस्ट यह कह सकते हैं कि इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में उन्होंने अन्य मूल्यवान उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया है? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मारा है। क्या मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है? क्या वे मालिक की जान लिए बिना संपत्ति नहीं ले सकते थे?'

संविधान का मसौदा तैयार करते समय, डॉ. अंबेडकर ने एकसमान कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए श्रम को समवर्ती सूची (Concurrent List) में रखा। उनकी दूरदर्शिता ने संविधान में बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करके उसे समाप्त कर दिया।

हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए 'Reform, Perform and Transform' मंत्र से प्रेरित होकर तथा डॉ. अंबेडकर के मूल्यों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने चार व्यापक श्रम संहिताओं (labour codes)–मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति–को लागू किया है। इन सुधारों का उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की दिशा में भारत की आर्थिक समृद्धि को मजबूत करना है। फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है, तथा मातृत्व संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है और क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य बनाया गया है।

'श्रमेव जयते' की स्थायी भावना से निर्देशित होकर हम राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के अनगिनत योगदान को सम्मानित करते हैं। परम पूज्य बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हमें इस महान राष्ट्र-निमार्ता के दृष्टिकोण और कार्यों पर विचार करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। उनके आदर्श हमें राष्ट्र की विकास यात्रा को तीव्रतर बनाने तथा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

लेखक केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार है।

आज का राशिफल

मेषः भूमि या सम्पत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण सौदे बनने की सम्भावना है। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का सही समय है, कुछ लोग विवाह को लेकर निर्णायक कदम उठा सकते हैं। ज्ञान-वृद्धि और नए कौशल सीखने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और आपके संपर्क बढ़ेंगे। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः आज आपकी कही बात किसी को आहत कर सकती है, इसलिए व्यवहार में संयम रखें। धन का अनावश्यक व्यय सम्भव है। किसी पुराने कार्य से जुड़ी चिंता दूर होगी, लेकिन व्यवसाय में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आज आप वही काम करेंगे जिसमें दिलचस्पी रखते हैं। परिवार को समय देने के लिए कार्य से छुट्टी भी ले सकते हैं। मानसिक शांति महसूस होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः अपनी निजी बातें सबके सामने साझा न करें, इससे मजाक या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। पोषण की कमी थकान बढ़ा सकती है। प्रेम संबंधों में असमंजस रहेगा। कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसका बाद में पछतावा हो। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः आप दूसरों की मदद करने में आगे रहेंगे। जीवनसाथी आपकी देखभाल करेगा। कामकाज की बाधाएँ कम होंगी। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने के अवसर बन सकते हैं। लोहा व शराब से जुड़े कारोबार में लाभ की प्रबल सम्भावना है। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः मन में थोड़ी दुविधा बनी रह सकती है, इसलिए विचारों में संतुलन रखें। कार्य से संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धी कमजोर पड़ेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी शुभ सूचना की संभावना है। दिनचर्या व्यवस्थित और नियंत्रित रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है। कारोबार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। घरेलू खर्चों में कटौती आवश्यक है। अनचाही यात्राओं का बोझ बढ़ सकता है। गूढ़ विषयों या रहस्यमयी ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ मतभेद सम्भव हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः आर्थिक स्थिति थोड़ी दबावपूर्ण रह सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन विचलित हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा। नकारात्मक विचार और अनजाना भय परेशान कर सकता है। *(सिटी दर्पण)*

धनुः कर्मक्षेत्र में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। अपने विचार जबरन दूसरों पर न थोपें। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। काम की गुणवत्ता को लेकर आप बेहद सतर्क रहेंगे। दांपत्य संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आप नई तकनीक सीखने का प्रयास करेंगे। परिवार के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा। करियर को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः आज पेट से संबंधित समस्या, विशेषकर वायु विकार परेशान कर सकता है। नई योजनाएं शुरू करने का अनुकूल समय है। उधार दिया धन वापस मिलने की उम्मीद है। दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। भविष्य को लेकर थोड़ा तनाव संभव है। *(सिटी दर्पण)*

मीनः दिन शुभ नहीं रहेगा। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक मान-सम्मान को ठेस लगने की आशंका है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी होगी। सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय न गँवाएँ। *(सिटी दर्पण)*

ताइवान संकट, जापान की सुरक्षा नीति और भारत के लिए बदलता इंडो-पैसिफिक समीकरण

डॉ प्रियंका सौरभ (हि.स)

जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव के केंद्र में आज ताइवान का प्रश्न है, जिसने पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति-संतुलन को नया मोड़ दे दिया है। भौगोलिक निकटता, समुद्री हितों और ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं के कारण जापान ताइवान की स्थिरता को अपने ही राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का विस्तार मानता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा ताइवान के आसपास की सैन्य गतिविधियों में तेजी- चाहे वह वायु क्षेत्र का उल्लंघन हो, मिसाइल परीक्षण हों या बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास ने जापान की खतरा-धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। साल 2022 में चीनी मिसाइलों का जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरना इस बात का सटीक संकेत था कि ताइवान संकट सीधे जापान के भू-राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करता है।

इसी कारण जापान ने अपनी सुरक्षा-रणनीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। दशकों से चले आ रहे शांतिवादी दृष्टिकोण के बावजूद उसने रक्षा-व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 2% तक ले जाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े सैन्य ढाँचों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर नई मिसाइल तैनाती की जा रही है और अमेरिका के साथ संयुक्त संचालन क्षमता को काफी बढ़ाया गया है। जापान समझता है कि यदि ताइवान में संघर्ष उत्पन्न होता है तो चीन की आक्रामकता सेंकाकू द्वीपों और जापानी जलक्षेत्रों की ओर भी बढ़ सकती है। इसलिए उसकी पूरी सुरक्षा-दृष्टि अब ताइवान जलडमरूमध्य की स्थिरता से गहराई से जुड़ चुकी है।

यह परिवर्तन उसकी विदेश-नीति में भी स्पष्ट दिखाई देता है। पहले जहाँ जापान ताइवान मुद्दे पर खुलकर बोलने से कतराता था, आज वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार 'ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता' को अनिवार्य बता रहा है। चीन के प्रति उसका कूटनीतिक रुख कहीं अधिक सख्त हुआ है। ताइवान को लेकर जापानी प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर चीन की धमकियों के बाद जापान द्वारा चीनी राजदूत को तलब करना इस बदलाव का प्रतीक है। साथ ही जापान अब क्वाड, आसियान देशों और यूरोपीय साझेदारों के साथ नई सुरक्षा-संरचनाएँ विकसित कर रहा है, ताकि चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता का संतुलन बनाया जा सके।

यह संपूर्ण परिदृश्य भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और जापान दोनों चीन की आक्रामक प्रवृत्ति से चिंतित हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच सुरक्षा-सहयोग स्वाभाविक रूप से गहरा हो रहा है। क्वाड की सामरिक महत्ता बढ़ी है और हिंद-प्रशांत में समुद्री निगरानी, नौसैनिक अभ्यास और तकनीकी सहयोग में तेजी आई है। जापान का सैन्य आधुनिकीकरण भारत के लिए रक्षा-उद्योग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलता है।

परंतु चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। भारत चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सीमा-क्षेत्र की शांति और आर्थिक सहयोग उसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता है। किंतु चीन-जापान तनाव का बढ़ना भारत-चीन संतुलन को और जटिल बनाता है। यदि भारत जापान और अमेरिका के साथ ज्यादा निकटता दिखाता है तो चीन सीमा पर दबाव बढ़ा सकता है। दूसरी बड़ी चिंता ताइवान जलडमरूमध्य में किसी भी सैन्य संकट से जुड़ी है। भारत के लिए यह समुद्री मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है; यहाँ किसी भी अस्थिरता से ऊर्जा आयात, व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक चिप आपूर्ति और संपूर्ण समुद्री परिवहन पर भारी असर पड़ेगा। इससे भारत की आर्थिक गति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को जोखिम हो सकता है।

तीसरी चुनौती अमेरिका की 'रणनीतिक अस्पष्टता' है। अमेरिका ने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि ताइवान पर हमले की स्थिति में वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं। यह अनिश्चितता पूरे क्षेत्र को दुविधा की स्थिति में डालती है। जापान और ताइवान तो इससे चिंतित हैं ही, भारत के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड की वास्तविक उपयोगिता इसी पर निर्भर करती है कि अमेरिका किस हद तक निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि अमेरिका अनिश्चित रहता है, तो चीन को क्षेत्र में और आक्रामक कदम उठाने का प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसका असर भारत की सुरक्षा-संतुलन पर भी पड़ेगा।

इन जटिलताओं के बीच भारत के लिए अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जापान की नई सक्रियता रक्षा-उद्योग सहयोग, समुद्री तकनीक, पनडुब्बी क्षमता और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को नई दिशा दे सकती है। भारत और जापान मिलकर एक स्थिर और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। व्यापार-मार्गों का विविधीकरण भी भारत के लिए अनिवार्य होगा, ताकि ताइवान जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके।

अंततः ताइवान संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इंडो-पैसिफिक का भविष्य अब पुराने समीकरणों पर नहीं चल सकता। जापान अपनी सुरक्षा-रणनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, चीन अपनी शक्ति का विस्तार जारी रखे हुए है और अमेरिका अपनी भूमिका को आंशिक रूप से पुनर्संतुलित कर रहा है। ऐसे परिदृश्य में भारत को अत्यंत संतुलित, चतुर और बहुस्तरीय कूटनीति अपनानी होगी- ऐसी कूटनीति, जो न तो चीन से अनावश्यक टकराव पैदा करे और न ही जापान, अमेरिका तथा अन्य साझेदारों के साथ बढ़ते सहयोग को धीमा करे।

इंडो-पैसिफिक के बदलते समीकरण भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और अवसर भी। यह समय भारत की सामरिक परिपक्वता, आर्थिक शक्ति-विस्तार और निर्णायक विदेश-नीति का है। यदि भारत इन सभी पहलुओं को संतुलित रूप से साध लेता है तो वह न केवल क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले वर्षों में इंडो-पैसिफिक के भविष्य का एक प्रमुख निर्धारक भी बनेगा।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

5 हजार से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली पहल शुरू करने वाला पहला राज्य बना पंजाबः हरजोत सिंह बैंस

पंजाब ने स्कूल शिक्षकों को करियर मैंटर के रूप में प्रशिक्षण देने के लिये आईआईटी मद्रास से मिलाया हाथ

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आईआईटी मद्रास प्रवर्तक के साथ साझेदारी कर पंजाब राज्य स्तर पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शिक्षक को एक प्रशिक्षित करियर मैंटर बनाने के लिए एक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

शुक्रवार को यह जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 5,000 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वे छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर सकें, करियर संबंधी विकल्पों के बारे में सटीक जानकारी दे सकें और करियर चयन में मार्गदर्शन कर सकें। बैंस ने कहा कि इस कार्यक्रम में शिक्षकों को बुनियादी करियर

❍ शिक्षकों को टॉप 100 उच्च-डिमांड वाले करियर और वैश्विक रुझानों तक आसान पहुंच प्राप्त होगीः बैंस

काउंसलिंग, कक्षा सत्रों के लिए कौशल तथा वन-टू-वन गाइडेंस के लिए मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक टॉप 100 उच्च-डिमांड वाले करियर, ढांचागत मूल्यांकन उपकरणों तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उभर रहे करियर रुझानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक निरंतर शैक्षणिक सहायता और डिजिटल संसाधन प्रदान करेगा।

बैंस ने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से हमारा लक्ष्य शिक्षकों को अपने स्कूलों में प्रभावशाली करियर

सलाहकार के रूप में सेवा देने में सक्षम बनाकर एक सार्थक और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना है। इस सहभागिता के माध्यम से शिक्षक एक ढांचागत करियर मार्गदर्शन वातावरण की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब अब शिक्षकों के लिए राज्य-स्तरीय करियर काउंसलिंग गाइडेंस कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी शिक्षक छात्रों को उनकी क्षमताओं की पहचान कराने, नए युग के पेशों की खोज करवाने तथा साक्ष्य एवं योग्यता आधारित मार्ग चुनने में सक्षम होंगे।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को विशेष रूप से लाभ होने की उम्मीद है जिससे उन्हें उच्च-गुणवत्ता वाली करियर गाइडेंस तक आसान पहुंच मिलेगी, जो पहले निजी काउंसलरों तक सीमित थी। अगले कुछ महीनों में हजारों शिक्षक नए कौशल, नए आत्मविश्वास और लाखों बच्चों के भविष्य को आकार देने की नई क्षमता हासिल करेंगे।

बोर्ड के साथ साझेदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए आईआईटी मद्रास प्रवर्तक के चीफ नॉलेज ऑफिसर श्री श्रीकांत ने कहा, 'हमारा उद्देश्य स्पष्ट और सीधा है, पंजाब में कोई भी बच्चा भ्रम या अधूरी जानकारी के आधार पर करियर का चयन न करे।'

पंजाब के किसानों का रेल रोको आंदोलन की सफलता का दावा

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

पंजाब में एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक) के बैनर तले किसानों ने आज राज्यव्यापी 'रेल रोको' आंदोलन किया है। उन्होंने आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच पंजाब के 19 जिलों में लगभग 26 स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाने की सूचना हैं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और मंजीत सिंह राय ने घोषणा की है कि आगामी दिसंबर महीने में विरोध प्रदर्शन तेज होंगे, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ

❍ मांगें नही पूरी की गई तो 19 को फिर रेल रोको आंदोलन होगा

प्रदर्शन (10 दिसंबर), डीसी कार्यालयों के बाहर धरने (17-18 दिसंबर), और यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो पूर्ण 'रेल रोको' आंदोलन (19 दिसंबर) शामिल हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार और पुलिस उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए उनके घरों पर छापेमारी कर रही है और उन्हें धमका रही है। उनकी प्रमुख माँगें में बिजली संशोधन विधेयक 2025: केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 को रद्द करना,

न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना, प्रीपेड मीटरः प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के निर्णय को वापस लेना, सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण को रोकना शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य मुद्दों किसानों और खेत मजदूरों के लिए कर्ज माफी और मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार और 700 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी की गारंटी भी लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल हैं।

यह आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की लगातार समस्याओं, जैसे ऋणग्रस्तता और पर्यावरणीय आपदाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न किसान संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न गुट, इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

डी.जी.पी. द्वारा पुलिस कर्मचारियों के लिए विभिन्न सख्त आदेश जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव ने पुलिस कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े नए और सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य पुलिस बल के पेशेवर छवि को बनाए रखना है। डीजीपी के

मुख्य आदेश में पुलिस कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान या पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर डांस या भांगड़ा करते हुए वीडियो/रील्स सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की फोटो अपराधियों या गैंगस्टरों के साथ पाई जाती है, तो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिसकर्मी ड्यूटी से संबंधित लाइव लोकेशन या किसी भी गतिविधि को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते। वर्दी के बिना भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जिससे विभाग की छवि को नुकसान पहुंचे। संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्टेट साइबर क्राइम विंग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रभावित हो सकती है। इन आदेशों के अलावा, पंजाब के डीजीपी ने राज्य चुनाव आयुक्त के निर्देशों के बाद, पटियाला के एसएसपी से जुड़े एक कथित ऑडियो क्लिप मामले की जांच एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) एसपीएस परमार को सौंप दी है, जिसमें विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की रणनीति पर चर्चा की गई थी। पुलिस का दावा है कि ऑडियो क्लिप एआई-जनरेटेड या फेक हो सकता है

पंजाब में ड्रग्स की आमद रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पूरा कंट्रोल जरूरीः सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

राष्ट्रीय भाजपा नेता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने कहा कि आज पंजाब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ हमारे युवाओं का भविष्य और हमारे राज्य की आत्मा हमारे कामों की हिम्मत और स्पष्टता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर माँ की उम्मीद, हर पिता के सपने और हर बच्चे के सुरक्षित भविष्य के अधिकार के लिए एक भावनात्मक लड़ाई है। आज एक प्रेस रिलीज में ग्रेवाल ने कहा कि वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति दिल से सम्मान, हार्दिक आभार और गहरे विश्वास के साथ सिर झुकाते हैं, जिनके मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व ने पहले ही भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता की एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब भारत सरकार की ओर नई उम्मीद से देख रहा है,

यह मानते हुए कि उनके मार्गदर्शन में ड्रग्स के खतरे को उसी दृढ़ संकल्प से हराया जा सकता है जिससे आतंकवाद और संगठित अपराध को कुचला गया था। ग्रेवाल ने कहा कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम पंजाब में नशीले पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पूरा कंट्रोल करना है। लेकिन उन्होंने उतनी ही ईमानदारी से यह भी कहा कि एक बार जब सीमाओं पर कंट्रोल हो जाए, तो ड्रग्स की पूरी आंतरिक सप्लाई चेन को बिना किसी देरी, बिना किसी समझौते और बिना किसी दया के तोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी ज्ञात हॉटस्पॉट पर तुरंत बड़े पैमाने पर छापे मारने, सप्लायरों, ट्रांसपोर्टरों, फाइनेंसरों और स्टोरेज ऑपरेटरों का बेरहमी से पता लगाने और एन.डी.पी.एस.और पी.एम.एल.ए.के तहत ड्रग तस्करों से संबंधित सभी बैंक खातों और संपत्तियों को फ्रीज करने की आवश्यकता है।

ग्रेवाल ने कहा कि वह भारत सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि ड्रग्स से संबंधित मामलों के लिए विशेष रूप से एक विशेष नारकोटिक्स कोर्ट स्थापित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मामले का फैसला नब्बे दिनों के भीतर किया जाए। इससे एक शक्तिशाली संदेश जाएगा कि धीमी न्याय का युग, वह युग जिसने माफिया को बेखौफ होकर बढ़ने दिया, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उन्होंने पंजाब के भविष्य के लिए ईमानदारी और प्यार भरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक और उतना ही महत्वपूर्ण कदम ड्रग माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच जहरीले गठजोड़ को तोड़ना है।

सडक हादसे में पत्नी की मौत, पति व दो बच्चे बाल-बाल बचे

अबोहर। गांव बल्लूआना के निकट आज दोपहर जालंधर से वापिस अबोहर आ रहे एक परिवार की कार अचानक आगे जा रहे दूसरे वाहन में टकरा गई जिसमें कार सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो बच्चे व महिला का पति बाल बाल बच गए। घटना का पता चलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार तारा एस्टेट कालोनी निवासी सुनीता मित्तल, उसका पति सुशील मित्तल, बेटी आस्था और आस्था की चचेरी बहन मुस्कान जालंधर में एक शादी समारोह में शामिल होकर आज अपनी कार से वापिस अबोहर आ रहे थे कि जब इनकी कार बल्लूआना कालोनी के निकट पहुंची तो अचानक झपकी लगने से उनकी कार आगे जा रहे किसी बड़े वाहन में टकरा गई जिसमें कार में आगे बैठी सुनीता मित्तल बुरी तरह से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले आए जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया।

संक्षिप्त-समाचार

54 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया, एक गिरफ्तार

लुधियाना। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, लुधियाना के अधिकारियों ने 4 दिसंबर को मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, में कई जगह छापे मारे, जहां 54 करोड़ रुपए के विशाल जीएसटी घोटाले का पता चला। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 300 करोड़ के नकली जीएसटी इनवॉइस का लाभ उठाया और ऐसे अवैध इनपुट टेक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग जीएसटी देयता को सेटऑफ करने के लिए किया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। यह कंपनी लोहा एवं इस्पात सम्बन्धी उत्पादों के विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थी। छापेमारी के बाद, कंपनी के एक मुख्य व्यक्ति को सेन्ट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। फिलहाल, जांच जारी है ताकि नेटवर्क की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके और अन्य शामिल संस्थाओं की पहचान की जा सके। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, लुधियाना, ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और कर धोखाधड़ी का पता लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोबारा व्यक्त करता है।

थाना मेहता पुलिस ने 32 बोर पिस्टल व दो जिंदा राउंड सहित एक आरोपी को दबोचा

अमृतसर। थाना मेहता पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति को 32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा राउंड सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरबजीत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी उदोनंगल के रूप में हुई है। मानयोग पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती सुहेल मीर (आई.पी.एस.) के निर्देशों और डी.एस.पी. जंडियाला रविंदर सिंह की अगुवाई में थाना मेहता पुलिस की टीम गश्त के दौरान अठवाल नहर के पास पहुंची। इस दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम सरबजीत सिंह बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 32 बोर पिस्टल और दो जिंदा राउंड बरामद हुए। इस संबंध में थाना मेहता में मुकदमा नंबर 143, तारीख 04.12.2025, धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है और जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हथियारबंद सेना झंडा दिवस पर अमृतसर ने किया अपने वीरों को नमन

अमृतसर। जिला रक्षा सेवाएं भलाई कार्यालय, अमृतसर की ओर से हथियारबंद सेना झंडा दिवस बड़ी गरिमा के साथ मनाया गया। हर वर्ष यह दिवस 07 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु इस बार 07 दिसंबर को रविवार होने के कारण इसे दो दिन पहले ही डिप्टी कमिश्नर-कम जिला सैनिक बोर्ड के प्रधान दलविंदरजीत सिंह के कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लेफ्टिनेंट कर्नल सरबजीत सिंह सैनी (रि.) द्वारा डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह के सीने पर झंडा लगाकर की गई। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब रक्षा सेवाएं भलाई विभाग की ओर से जारी 'रणजोधे' किताब का भी रिलीज किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेना झंडा दिवस देश के उन अमर शहीदों की याद को ताजा करता है, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने बताया कि यह अवसर उन सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान जताने का है जो देश की रक्षा में हर कठिन परिस्थिति में डटे रहे। उन्होंने कहा कि कई जवान देश की अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुए, कई जीवनभर के लिए घायल हो गए। ऐसे परिवारों की देखभाल करना समाज और सरकार दोनों का पवित्र कर्तव्य है। झंडा दिवस के अवसर पर एकत्रित धनराशि 'आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड' में जमा कर शहीदों के परिजनों, विकलांग और जरूरतमंद पूर्व सैनिकों की भलाई पर खर्च की जाती है। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने अमृतसर जिले के नागरिकों, निजी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, विभागों और संस्थाओं से अपील की कि वे खुले दिल से योगदान दें और उन वीर शहीदों के परिवारों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करें।

रूपनगर ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सभी उम्मीदवारों ने माथा टेका

रूपनगर। शिरोमणि अकाली दल के रूपनगर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगर ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सभी उम्मीदवारों ने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा के नेतृत्व में गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहिब में माथा टेका और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास की! इस मौके पर संबोधित करते हुए डॉ. चीमा ने कहा कि रूपनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी अकाली वर्कर इन चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब आम आदमी पार्टी की कसमों की राजनीति को समझ चुके हैं और अब उनकी कसमों में नहीं आएंगे और अपनी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएंगे। इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त तख्तगढ़ जोन से जिला परिषद उम्मीदवार सुरिंदर कुमार टिब्बा नंगल मियांपुर जोन से चरणजीत कौर बोला, कलवां जोन से हुसन चंद, मथान ब्लॉक समिति के सभी उम्मीदवार लखविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह मसूता, सरोजन सिंह, हरविंदर कौर, सुनीता रानी, परमजीत कौर, भूपिंदर सिंह बिट्टू मौजूद रहे।

डॉ. गिरिश मित्तल जैतो ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की मुलाकात

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

पाइनलैंड इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. गिरिश मित्तल ने हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। यह बैठक ब्रहमाकुमारीज के विंग के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित की गई।इस दौरान शिक्षा और लीगल के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हमारे प्रयासों की सराहना की और मूल्यों पर आधारित जिन पहलों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर डॉ. गिरिश मित्तल ने बताया कि देश में राष्ट्रीय अभियान झ मूल्य आधारित न्याय : विधि की आत्मा और मूल्य आधारित न्याय एवं शिक्षा के माध्यम से न्याय और शिक्षा में नैतिक

मूल्यों को सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान राष्ट्र और समाज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. मित्तल ने आगे बताया कि विद्यालय का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा पहुँचाना है, जिससे देश का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके।

दर्ज मुकदमे में 274 ग्राम हैरोइन सहित एक और आरोपी दबोचा

अमृतसर। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा नशे के विरुद्ध चलाई जा रही राज्यव्यापी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' एवं माननीय डी.जी.पी. पंजाब की सख्त हिदायतों के अंतर्गत, वरिष्ठ पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती श्री सुहेल मीर (आई.पी.एस.) और डी.एस.पी. (डी) श्री गुरिंदरपाल सिंह की अगुवाई में स्पेशल सेल अमृतसर देहाती ने नशा तस्करी के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दिनांक 01.12.2025 को स्पेशल सेल की टीम ने गश्त के दौरान गांव खासा के पास प्रदीप सिंह निवासी हरदो रत्तन, जग रूप सिंह निवासी वेरका और करणबीर सिंह निवासी नंगल वंझावाला को 255 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किया था, जिसके संबंध में थाना घरिंडा में मुकदमा नंबर 393 दिनांक 01.12.2025 धारा 21(सी)/29/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज किया गया था और जांच जारी है। इसी जांच के दौरान पूछताछ में एक अन्य साथी करणबीर सिंह निवासी धनोए कला का नाम सामने आया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे 274 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया।

प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
फरीदकोट

सुक्खनवाला मर्डर केस का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। पूरे गांव में शोक की लहर थी और हर गांव वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस मौके पर फरीदकोट के टछअ गुरदित सिंह सेखों भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और परिवार के साथ दुख बांटा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि फरीदकोट जिले के सुक्खन वाला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने मामले के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान डबवाली, सिरसा (हरियाणा) के रहने वाले विश्वजीत सिंह के रूप में हुई है और वह मुख्य आरोपी हरकमलप्रीत सिंह का करीबी दोस्त है। घटना वाली रात वह हरकमलप्रीत के साथ कार में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना वाली रात दोनों द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है।

इससे पहले, पुलिस ने मृतक की पत्नी रूपिंदर कौर को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि उसके प्रेमी हरकमलप्रीत सिंह ने 2 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने तब से उसका रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने और घटनाओं के सिलसिले को जोड़ने के लिए दोनों से आमने-सामने पूछताछ कर रही है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कूड़ा जलाने के खिलाफ कार्रवाई जारी

❍ अमृतसर ज़िले में चलाया गया जागरूकता अभियान

सिटी दर्पण संवाददाता
अमृतसर

जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के अपने मजबूत संकल्प को दोहराते हुए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ज़िले में म्यूनिसिपल ठोस कचरे को खुले में जलाने के विरुद्ध अपनी विशेष प्रवर्तन और जागरूकता मुहिम जारी रखी है।

नगर पंचायत राजासांसी और नगर पंचायत अजनाला में आयोजित गतिविधियों के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर ने आज इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नगर परिषद जंडियाला गुरु, नगर पंचायत रैय्या और नगर पंचायत बाबा बकाला साहिब में कार्यक्रम आयोजित किए।

इन कार्यक्रमों के दौरान सहायक पर्यावरण इंजीनियर सुखमनी सिंह ने

सफाई टीमों से सीधे संवाद करते हुए कूड़ा जलाने से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कूड़ा जलाने के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और Solid Waste Management Rules, 2016 के तहत स्रोत पर कचरे की छंटाई, घर-घर कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की अनिवार्यता पर चर्चा की।

सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कचरा जलाने पर पूर्ण रोक लगाने के लिए सामूहिक शपथ ली। संबंधित सुपरिंटेंडेंट्स और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने बोर्ड के निर्देशों का पूर्ण पालन और सख़्त कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिया।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुनः स्पष्ट किया कि सख़्त निगरानी, आकस्मिक निरीक्षण और समयबद्ध प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि कचरा जलाने से संबंधित जनता की शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान किया जा सके और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान किया जा सके।

पाईटैक्स में कृषि, पोषण और कल्याण तालमेल विषय पर सम्मेलन का आयोजन

पंजाब के पांच हजार स्कूलों में बनाए जाएंगे पौष्टिक बगीचे: बी.एम. शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
अमृतसर

पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन बी.एम.शर्मा ने कहा है कि पंजाब सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के भविष्य को देखते राज्य के पांच हजार 73 स्कूलों में पौष्टिक बगीचों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं।

शर्मा पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किए जा रहे 19वें पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के दौरान आज कृषि, पोषण और कल्याण तालमेल विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब में खाद्य भंडार की कोई कमी नहीं है लेकिन पंजाब वासियों को क्वालिटी फूड देना बड़ी

चुनौती है। उन्होंने कहा कि किसानों को जहां फसली विभिन्नता अपनाने पर जोर दिया जा रहा है वहीं बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन स्कूलों का चयन किया गया है जहां खाली जमीन पड़ी है। इसके लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग देकर हर्बल गार्डन, फ्रूट गार्डन, वेजीटेबल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। यह फल, सब्जियां बच्चों के मिड डे मील का हिस्सा बनेंगी। जिससे उन्हें स्कूल स्तर पर ही क्वालिटी फूड दिया जा सकेगा। शर्मा ने बताया कि राज्य में बहुत से स्कूल तो ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास तीन से चार एकड़ सरप्लस जमीन पड़ी है। अब इस जमीन पर कृषि विभाग, बागवानी विभाग तथा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर पौष्टिक बगीचे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1100 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जहां अतिरिक्त जमीन पर पौष्टिक बगीचे बनाए जाएंगे। इससे पहले पीएचडीसीसीआई की फार्मास्यूटिकल, हेल्थ एंड वेलनैस कमेटी के संयोजक सुप्रीत सिंह ने कहा कि बदलती जीवन शैली में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खाने में 20 प्रतिशत टेस्ट और 80 प्रतिशत पौष्टिकता होनी जरूरी है। ग्राफिक्स एरा विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. नरपिंदर सिंह ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के समापन पर पीएचडीसीसीआई आयुर्वेदा, यूनानी फार्मा कमेटी की संयोजक डॉ. विभा बावा ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपेडा के क्षेत्रीय प्रभारी हरप्रीत सिंह, गुरुनानक देव विवि के डॉ. सिद्धांत बनूरा, अमृतसर कृषि विभाग के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डा. गुरसाहिब सिंह, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगमोहन सिंह नागी, राकेश ठुकराल, फूड कमीशन के सदस्य विकास दत्त जुनेजा समेत कई गणमान्य मौजद थे।

नशे के आदी दो लोगों को नशीले पाउडर साहित किया गिरफ्तार

मोरिंडा। पंजाब सरकार द्वारा ड्रग तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान 'वॉर अगेंस्ट ड्रग्स' के तहत, जिला रूपनगर प्रभारी गुलनीत सिंह खुराना के निर्देशों और डीएसपी मोरिंडा गुरजीत सिंह के नेतृत्व में, मोरिंडा सिटी पुलिस ने मोरिंडा-चुन्नी रोड पर स्थित श्मशान घाट से एक युवक को 10.11 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर गुरमुख सिंह थाना प्रभारी मोरिंडा शहरी ने बताया कि एएसआई अंग्रेज सिंह व विशाल जोशी, कांस्टेबल प्रितपाल सिंह और कांस्टेबल अमन कुमार की एक पुलिस पार्टी सिविल अस्पताल मोरिंडा से रतनगढ़ चौक तक नाकाबंदी और पेट्रोलिंग करके ड्रग तस्करों और आसमाजिक तत्वों की जांच कर रही थी। जब पुलिस पार्टी ने सिविल अस्पताल के पास मोरिंडा श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़क पर एक युवक को खड़ा देखा, तो उसने पुलिस पार्टी को देखकर अपनी पैंट की जेब से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का लिफाफा निकालकर सड़क पर फेंक दिया और फिर भागने की कोशिश की।

एलसीए तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान के लिए भारत को मिला पांचवां जीई-404 इंजन

बुनियादी समस्याओं का समाधान होने के बाद विमान के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

अमेरिकी इंजन निमार्ता कंपनी जीई एयरोस्पेस ने शुक्रवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क-1 ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को पांचवां जेट इंजन सौंप दिया।

इस वित्त वर्ष के अंत तक भारत को 12 जीई-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। एचएएल को मार्च से नए विमान की आपूर्ति करनी थी, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन की अमेरिका से आपूर्ति में देरी की वजह से इंतजार लंबा हो गया।

अब इंजन को लेकर बुनियादी समस्याओं का समाधान होने के बाद विमान के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। भारत ने फरवरी, 2021 में एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का एक समझौता किया था। इस अनुबंध में 73 लड़ाकू जेट

एलसीए ने एचएएल को सौंपा पांचवा जेट इंजन

और 10 प्रशिक्षक विमान शामिल थे। भारतीय वायु सेना को 2024 में पहली खेप मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच कंपनी जीई एयरोस्पेस (जीई) ने एफ-404 इंजन का उत्पादन बंद कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने इसी साल 25 सितंबर को एचएएल के साथ अतिरिक्त 97 एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के नए ऑर्डर का अनुबंध किया है, जिसमें 68 सिंगल-सीट लड़ाकू विमान और 29 ट्विन-सीट ट्रेनर विमान हैं, जिनकी डिलीवरी 2027-28 में शुरू होकर छह वर्षों में पूरी होगी। इस तरह एचएएल को भारतीय वायु सेना के लिए 180 विमानों का निर्माण करना है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कंपनी ने इसी साल 26 मार्च को पहला इंजन भारत को सौंपा। इसके बाद 13 जुलाई को जीई ने दूसरा इंजन भेजा। एचएएल

फोटोः हि.स.

को एलसीए मार्क-1ए के लिए तीसरा जीई-404 इंजन 11 सितंबर को मिला। कंपनी ने उसी समय एक और इंजन सितंबर के अंत तक देने का वादा किया था, जिसकी आपूर्ति 30 सितंबर को की गई। भारत को चार इंजन मिलने के बाद एलसीए मार्क-1ए विमानों के उत्पादन और आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद बढ़ी है। अमेरिकी इंजन निमार्ता कंपनी जीई एयरोस्पेस ने पांचवां इंजन आज एचएएल को सौंप दिया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत को 12 जीई-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। ये इंजन भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में लगाए जायेंगे, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है। एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. डीके सुनील ने कहा कि एचएएल जीई के एफ-414 इंजनों के लिए 80 फीसदी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी बातचीत कर रहा है, जो उन्नत एलसीए मार्क-2 और स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) को शक्ति प्रदान करेगा।

डॉ. सुनील ने कहा कि जीई ने हमें एक साल में 12 इंजन देने का वादा किया था, लेकिन अब शायद हमें वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 इंजन मिल जाएंगे। इस साल हमें 10 इंजन मिल सकते हैं। बाकी इंजन हमें अगले साल मार्च तक मिल जाएंगे। हम 10वें विमान का ढांचा बना चुके हैं और 11वां विमान तैयार है। इंजन को लेकर बुनियादी समस्याओं का समाधान हो गया है, इसलिए अब उत्पादन में तेजी आएगी। जीई ने अगले साल 20 इंजन देने का वादा किया है, जिसके लिए शीर्ष प्रबंधन के साथ एक बैठक की है।

मप्र में अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्कर लाचुंगपा भारत-चीन सीमा पर सिक्किम से हुई गिरफ्तार

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने की कार्रवाई

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने भारत-चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) से गिरफ्तार किया है। 10 साल से वांछित इस आरोपित को अंतरर से कई महीनों की कड़ी मेहनत के उपरांत 2 दिसम्बर 2025 को सफलतापूर्वक कार्रवाई में गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण के लिये लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में यह कार्रवाई की गई है। जनसंपर्क अधिकारी के.के. जोशी ने शुक्रवार को बताया कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में बाघ एवं पेंगोलिन के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों व पेंगोलिन के स्केल की नेपाल के रास्ते चीन में अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध जुलाई 2015 में प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें यांगचेन लाचुंगपा वांछित थी। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए वन मुख्यालय ने इसे मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को विवेचना के लिये सौंपा गया था। एसटीएसएफ ने एक संगठित एवं अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 31 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि यांगचेन लाचुंगपा अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। यांगचेन लाचुंगपा के गिरोह के कई देशों में फैले नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल के द्वारा यांगचेन लाचुंगपा विरुद्ध रेड नोटिस भी जारी किया गया है, जिससे उसे किसी भी देश में सबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सके। यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की निवासी है एवं भारत में मुख्यतः दिल्ली एवं सिक्किम में रहती थी। यांगचेन को पहली बार सितम्बर 2017 में भी हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड के लिये पेश किया गया था, लेकिन न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी।

उसकी अग्रिम जमानत को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि अपराधी यांगचेन लाचुंगपा गिरफ्तारी से बचने लगातार एजेंसियों को चकमा दे रही थी, अंत में 2 दिसम्बर 2025 को उसे मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं केंद्र सरकार की वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की संयुक्त टीम ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कम तापमान के क्षेत्र में जाकर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर लाचुंग, मंगन (सिक्किम) से गिरफ्तार कर न्यायालय गंगटोक के समक्ष पेश कर मध्य प्रदेश शासन का ठोस पक्ष रखने के बाद ट्रांजिट वारंट 3 दिसम्बर 2025 को रात्रि में प्राप्त कर उसे मध्यप्रदेश लाया जा रहा है।

आदिनाथ मंदिर को तोड़ कर बनी है आदिना मस्जिदः शामिक भट्टाचार्य

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य शामिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को सदन में आदिना मस्जिद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आदिना मस्जिद जिस स्थान पर बनी है, वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था, जिसे तोड़कर यह ढांचा खड़ा किया गया। शामिल ने शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में एक बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के दावे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह कोई मंदिर-मस्जिद का झगड़ा या हिंदूझमुस्लिम का विभाजन नहीं है। सिकंदर एक लुटेरा था, उसने आदिनाथ मंदिर को नष्ट कर यहां मस्जिद बनवाई। आज भी वहां मंदिर के अवशेष दिखते हैं। कमल की आकृति, देवीझदेवताओं के चिह्न, यहां तक कि गणेश जी की मूर्ति भी है। भाजपा सदस्य ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के दावे की निंदा की, जिसने चुनावी राज्य में राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भाजपा ने दावा किया है कि यह पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि 'यह मस्जिद नहीं, मंदिर ही है। पश्चिम बंगाल के 72 जन समुदाय भी अपना मंदिर वापस चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। इस मस्जिद को 1369 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था।

बाल-विवाह मुक्त होंगे बंगाल के 23 जिले, शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा अभियान

कोलकाता। भारत को वर्ष 2030 तक बाल-विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) ने अगले एक वर्ष के भीतर देश के एक लाख गांवों को बाल-विवाह मुक्त घोषित करने का व्यापक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V (2019-21) के आधार पर पहचाने गए उच्च-प्रभावित जिलों में पश्चिम बंगाल के 23 जिलों को विशेष निगरानी और कार्रवाई के लिए शामिल किया गया है। यह घोषणा केंद्र सरकार के बाल्यविवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर की गई, जिसे 100-दिवसीय कार्ययोजना के तहत शुरू किया गया था। जेआरसी देशभर में 250 से अधिक एनजीओ के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है और पश्चिम बंगाल में 14 साझेदार संगठनों के सहयोग से कार्य कर रहा है। पिछले एक वर्ष में इस नेटवर्क ने राज्य में 11,938 बाल-विवाह रोके हैं। देशभर में पिछले वर्ष में एक लाख से अधिक बाल-विवाह रोकने में भी यह नेटवर्क सफल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणझ्र के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बाल-विवाह की दर 41.6 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

इंडिगो एयरलाइंस की अव्यवस्था का असर नेपाल की उड़ानों में भी दिखा

दिल्ली और मुंबई से काठमांडू आने वाली उड़ानें करीब 1 घंटे की देरी से रवाना

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

भारत में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संचालन व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालझभारत रूट की उड़ानों पर भी देखा गया है। गुरुवार को दिल्ली और मुंबई से काठमांडू आने वाली अन्य तीन उड़ानें भी करीब 1 घंटे की देरी से रवाना हुईं। शुक्रवार को भी उड़ानें प्रभावित हो रही है।

शुक्रवार सुबह 9 बजे उतरने वाली पहली उड़ान तीन घंटे की देरी के बाद दोपहर 12 बजे लैंड हो सकी है। काठमांडू विमानस्थल के अनुसार गुरुवार दोपहर 4 बजे काठमांडू में

फोटोः हि.स.

उतरने वाली उड़ान संख्या 6ए-1155 शाम साढ़े 7 बजे लैंड कर सकी। इसी तरह दिल्ली से ही दोपहर 1230 बजे लैंड करने वाली इंडिगो की दूसरी विमान के ढाई घंटे की देरी से लैंड की सूचना दी गई है। शुक्रवार को ही मुंबई से आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ए 1915 के लैंड का समय 1330 है, उसके भी करीब दो घंटे विलंब से लैंड करने वाली है। दिल्ली-काठमांड-दिल्ली की तीन और मुंबइ-काठमांडू की एक उड़ान सहित प्रतिदिन आठ दोतरफा उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो के काठमांडू कार्यालय ने जानकारी दी है कि उड़ानों पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन भारत की तरह नेपाल में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की स्थिति नहीं बनेगी। भारत में कड़े क्रू-रोस्टर नियम लागू होने से उत्पन्न तनाव और एयरबस के आपातकालीन सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण शुरू हुई उड़ान अव्यवस्था का असर नेपाल में भी सीधा देखा गया है।

नेपाल में इंडिगो के जीएसए प्रतिनिधि भोला विक्रम थापा के अनुसार एयरबस के सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण नेपाल आने वाली इंडिगो उड़ानों में देरी तो हुई है, लेकिन भारत की तरह उड़ान रद्द करने की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में इंडिगो की उड़ानें फिर सामान्य हो जाएंगी। भारत के हवाई अड्डों जैसा बड़ा असर नेपाल में नहीं होगा। यह केवल सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई देरी है, उड़ानें रद्द नहीं होंगी। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय एयरलाइन है।

संक्षिप्त-समाचार

बैंक कर्मी ने युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर किया वायरल

नोएडा। थाना सेक्टर 20 में एक युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसने उसकी कुछ निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इस मामले में युवती ने युवक के खिलाफ थाना में तहरीर भी दी है। पीड़ित महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने शुक्रवार को बताया कि निठारी गांव में रहने वाली एक युवती ने गुरुवार देर रात को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक कंपनी में काम करती है। दिल्ली निवासी सूरज सिंह जो की एक बैंक में काम करता था। वह कुछ दिन पहले उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों का खाता खुलवाने के लिए कंपनी में आया था। तभी से उसकी उससे जान पहचान हो गई। दोनों आपस में मिलते रहे। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और इस दौरान उसने उसकी कुछ निजी फोटो खींच ली थी। अब आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। जब उसने मना किया तो इस बात से नाराज होकर उसने इंस्टाग्राम पर उसकी फर्जी आईडी बनाई और उन सभी निजी फोटो को वायरल कर दिया। इतना ही नही आरोपित ने उन सब फोटो को उसके होने वाले पति विनय और उसके पिता बलविंदर सिंह को उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दी। आरोपित मौजूदा समय में सेक्टर 50 स्थित दूसरी बैंक में नौकरी कर रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ब्रिटेन में अवैध रूप से काम करने के आरोप में पकड़े गए लोगों में भारतीय भी शामिल

लंदन। ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर की गई कार्रवाई में अवैध रूप से काम करते पकड़े गए 171 लोगों में भारतीय भी शामिल हैं। इन्हें देश से बाहर भेजने के लिए हिरासत में लिया गया है। ब्रिटेन सरकार ने यह जानकारी दी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की आव्रजन प्रवर्तन टीम ने पिछले महीने सात दिन तक 'ऑपरेशन इक्वलाइज' चलाया, जिसमें ब्रिटेन के गांवों, कस्बों और शहरों में सामान पहुंचाने का काम करने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। अवैध रूप से काम करते पाए गए (जिनमें बांग्लादेशी और चीनी नागरिक भी शामिल थे) लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मूल देशों में भेजने के लिए हिरासत में ले लिया गया। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, 17 नवंबर को, न्यूहैम (पूर्वी लंदन) के हाई स्ट्रीट पर अधिकारियों को तैनात किया गया था। बांग्लादेशी और भारतीय नागरिकता वाले चार लोगों को अवैध रूप से काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चारों को वापस भेजने के लिए हिरासत में लिया गया। इसने गिरफ्तार किए गए कुल 171 लोगों का ब्योरा दिया। इसमें कहा गया, और 25 नवंबर को अधिकारी नॉर्विच सिटी सेंटर (पूर्वी इंग्लैंड) पहुंचे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण अभियान चलाया। सामान पहुंचाने का काम करने वाले भारतीय नागरिकता वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो को देश से बाहर भेजने के लिए हिरासत में लिया गया। तीसरे व्यक्ति को सख्त आव्रजन जमानत पर रखा गया।

जर्मनी की संसद ने सैनिकों की अधिक भर्ती वाली योजना को दी मंजूरी

बर्लिन। जर्मनी की संसद ने रूस से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपने सशस्त्र बलों में सैनिकों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश के तहत शुक्रवार को एक योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना में युवाओं के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच का भी प्रावधान है। वैसे इस योजना में अनिवार्य सैन्य भर्ती पर रोक है लेकिन जरूरत पड़ने पर कम से कम सीमित संख्या में अनिवार्य सैन्य सेवा की संभावना का विकल्प खुला रखा गया है। संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में 272 के मुकाबले 323 मतों से इस योजना को मंजूरी दी गयी जबकि एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया। यह चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त में पारित की गई एक परियोजना का संशोधित संस्करण है। जर्मनी ने वर्षों की उपेक्षा के बाद अपनी सेना के उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का निर्णय लिया है और सरकार ने अपना ध्यान अधिकाधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित कर किया है।

ईरान ने होर्मुज खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी

तेहरान। ईरान की नौसेना ने अपने युद्धाभ्यास के दूसरे दिन ओमान सागर और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागीं। सरकारी टेलीविजन चैनल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी टीवी चैनल ने खबर दी कि अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बृहस्पतिवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास के तहत ईरान की मुख्य भूमि के भीतरी हिस्सों से मिसाइलें दागीं और ओमान सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट पड़ोसी क्षेत्र में तय लक्ष्यों पर निशाना साधा। खबर के मुताबिक अभ्यास के दौरान कद्र-110, कद्र-380 और गदीर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जिनकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर (1,250 मील) तक है। इसने कहा कि रिवोन्यूशनरी गार्ड ने 303 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की है, हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। टेलीविजन चैनल पर प्रसारित तस्वीरों में मिसाइलों के प्रक्षेपण और लक्ष्यों पर उनके प्रहार को दिखाया गया है। यह युद्धाभ्यास जून में इजराइल-ईरान युद्ध के बाद दूसरा इस तरह का सैन्य अभ्यास है। युद्ध के दौरान ईरान के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों सहित लगभग 1,100 लोग मारे गए थे। ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में 28 लोग मारे गए थे।

आपदा मोचन बल ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में खोज और बचाव अभियान पूरा किया

कोलंबो। चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका में खोज, बचाव और राहत अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम शुक्रवार को स्वदेश रवाना हो गयीं। भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी। श्रीलंका चक्रवात दित्वा के कारण व्यापक बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के ध्वस्त होने के संकट से जूझ रहा है। इस आपदा के कारण शुक्रवार तक 450 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, कई जिलों का संपर्क टूट गया है तथा देश की आपदा मोचन क्षमता पर भी गंभीर दबाव पड़ा है।

नेपाल में आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचीं

राजनीतिक दलों को 7 दिसंबर को आवेदन जमा करना होगा

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल मार्च में होने हैं, जिसमें अब केवल 90 दिन शेष रहने के साथ ही तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने भी आंतरिक कार्य योजनाएं सक्रिय रूप से आगे बढ़ाई है।

आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई के अनुसार आयोग 6 दिसंबर से समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यक्रम लागू करने जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार राजनीतिक दलों को 7 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से सम्बन्धित आवेदन जमा करना होगा। आवेदन देने वाले दलों की सूची 10 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। आवेदन देने वाले दल अपनी बन्द सूची 28 और 29 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तिम सूची 13 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मीदवार नामांकन 20 जनवरी को दर्ज किए जाएंगे और उसी दिन नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होगी। नामांकन के विरुद्ध शिकायतें 21 जनवरी को दर्ज की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की प्रारम्भिक सूची 22 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवार 23 जनवरी को अपना नाम वापस ले सकेंगे, जिसके बाद अन्तिम सूची प्रकाशित की जाएगी और निर्वाचन चिह्न आवंटित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 3 मार्च तक का समय दिया गया है। 3 मार्च की शाम 5 बजे से मौन अवधि शुरू हो जाएगी। 5 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शाम 7 बजे तक मतदान का देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। मतदान के बाद सभी मतपेटिकाएं जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर एकत्रित कर ली जाएगी।

रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती से वाहन उद्योग की वृद्धि को मिलेगी गति : सियाम

नई दिल्ली। वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती के फैसले का स्वागत किया है। सियाम ने कहा कि इस फैसले से और हाल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने से वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए वाहन कर्ज सस्ता होंगे और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी। वाहन उद्योग संगठन सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा कि आरबीआई की ओर से आज घोषित 0.25 फीसदी की रेपो रेट कटौती तथा पहले की गई रेपो रेट में कमी देश में उपभोक्ता धारणा को प्रोत्साहित करने वाले अनुकूल मौद्रिक माहौल को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित आयकर राहत उपायों और ऐतिहासिक जीएसटी 2.0 सुधारों के साथ आरबीआई का यह कदम ग्राहकों की खरीद क्षमता को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सियाम को उम्मीद है कि मौद्रिक और राजकोषीय उपायों से भारतीय वाहन उद्योग की वृद्धि को और गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा राज्य के विकास में आई है तेजी : विष्णुदेव साय

एजेंसी (हि.स.)
ग्वालियर

फोटोः हि.स.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, जहाँ वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विकास की राह में बाधा बने नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है और यह अब अपने अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारे दो साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा वर्षों से थी, वह थी नक्सलवाद। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, लगातार चल रही सुरक्षा रणनीतियों और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। प्रदेश में लोगों के बीच सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में अत्यंत संकल्पित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का उल्लेख ,किया जिसमें मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो संकल्प मोदी जी और अमित शाह जी ने लिया है, वह पूरा होते साफ दिखाई दे रहा है। खासकर बस्तर जैसे क्षेत्र में, जहाँ कई दशकों से नक्सलियों का दबदबा था और जो विकास की मुख्यधारा से काफी दूर था, अब वहाँ विकास की गंगा बहने वाली है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर का अनुमान घटाकर दो फीसदी किया

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

फोटोः हि.स.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जीएसटी रेट कटौती और खाद्य कीमतों में तेज गिरावट के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई दर में गिरावट खाद्य कीमतों में सुधार की वजह से आई है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यहां मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में लगाए गए अनुमान से कम रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में गिरावट है। मल्होत्रा ने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित (सीपीआई) खुदरा महंगाई अब दो फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने इसके तीसरी तिमाही में 0.6 फीसदी और चौथी तिमाही में 2.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए, सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर क्रमशः 3.9 फीसदी और 4.0 फीसदी रहने का अनुमान है। महंगाई के परिदृश्य पर संजय मल्होत्रा ने कहा कि उच्च खरीफ उत्पादन, अच्छी रबी बुवाई, जलाशयों के पर्याप्त स्तर एवं मिट्टी में अनुकूल नमी से खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ धातुओं को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंस की कीमतों में आगे चलकर नरमी आने की संभावना है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव और भी कम है, क्योंकि कीमती धातुओं की कीमत में वृद्धि का प्रभाव लगभग 0.50 फीसदी है, जिसमें जोखिम दोनों ओर समान है।

कार्यक्रम | **महाराष्ट्र के चिखली में मनेगा राष्ट्रसेवा की अखंड साधना उत्सव**

'मैं' से 'हम' की ओर लौट रहा भारत

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

सनातन परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव से उभरता भारत तेज रफ्तार, उपलब्धियों और व्यक्तिगत सफलता के शोर से भरा हुआ है। ऐसे समय में जब समाज 'मैं' से 'हम' की ओर लौटने का रास्ता खोज रहा है, तब महाराष्ट्र के चिखली में 6 और 7 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने जा रहा सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह उस जीवन दर्शन की याद दिला रहा है, जिसमें स्वयं नहीं, राष्ट्र पहले होता है। वरिष्ठ संघ प्रचारक लक्ष्मीनारायण भाला लक्खीदा के 81वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर होने वाला यह आयोजन राष्ट्र साधना की परंपरा का सार्वजनिक उत्सव बनेगा।

वर्ष 1968 में गृहत्याग कर संघ कार्य में प्रवृत्त हुए लक्खीदा का जीवन उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने सुविधाओं को नहीं, संघर्ष को चुना, पद नहीं, प्रवृत्ति को अपनाया, प्रसिद्धि नहीं, कर्तव्य को सार्थक माना। आज जब समाज तात्कालिक लाभ और व्यक्तिगत उन्नति के गणित में उलझा हुआ है, तब ऐसे जीवन चरित्र याद दिलाते हैं कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं, एक निरंतर चलने वाली साधना है। श्री भाला ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्रकार्य की शुरूआत की थी। वे पिछले 57 वर्षों से निरंतर समाज, संगठन और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय रहे हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संत परंपरा, संगठन शक्ति और सांस्कृतिक चेतना- तीनों धाराओं का संगम बनकर उभर रहा है।

संस्कृति से राष्ट्रबोध तक का सेतु

कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाली केशव कल्प पर आधारित शास्त्रीय नृत्य-नाटिका अपने आप में एक सांस्कृतिक वक्तव्य है। डॉ. हेडगेवार जैसे राष्ट्रद्रष्टा के जीवन को कला के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना यह दशार्ता है कि संघ विचार केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि संवेदना और सौंदर्य का भी विषय है। आज जब वैश्विक मंच पर भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है, तब ऐसे आयोजन यह सिद्ध करते हैं कि राष्ट्रनिर्माण केवल नीति से नहीं, संस्कृति से भी होता है।

सार्थक जीवन का प्रतीक 'सहस्र चंद्र दर्शन'

भारतीय परंपरा में सहस्र चंद्र दर्शन केवल दीघार्यु नहीं, बल्कि सार्थक जीवन का प्रतीक है। इसका निहितार्थ है- इतने वर्षों तक समाज के लिए उपयोगी रहना कि जीवन स्वयं एक ग्रंथ बन जाए। लक्खीदा का जीवन इस अर्थ में एक चलता-फिरता राष्ट्र पाठ्यक्रम है, जिसका प्रत्येक अध्याय त्याग, अनुशासन, सेवा और समर्पण से लिखा गया है।

दादा आप्टे के बीज को श्रीकांत जोशी ने सींचा

पश्चिमी प्रभाव के बीच भारतीय विचार-दृष्टि के उर्वर भूमि तैयार करने में शामिल रहे चिंतक दादा साहेब आप्टे (शिवराम शंकर आप्टे) ने 1948 में हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी के रूप में जो बीज बोया था, आज वह भारतीय भाषाओं की आवाज बन चुका है। श्रीकांत जोशी और लक्ष्मीनारायण भाला इसके मार्गदर्शक बनकर उभरे। फरवरी 2013 में श्रीकांत जोशी जी के देहावसान के बाद हिन्दुस्थान समाचार की जिम्मेदारी जिन मजबूत कंधों पर आई, वे थे लक्ष्मीनारायण भाला लक्खी दा। यह समय एजेंसी के लिए संक्रमण का दौर था, जिसे उन्होंने दृढ़ता, अनुशासन और दूरदृष्टि से संभाला। उनके नेतृत्व में हिन्दुस्थान समाचार की सरकारी, सामाजिक और मीडिया जगत में साख और मजबूत हुई।

हम भारत में इक्वेस्ट्रियन के लिए अनुकूल स्पोर्ट्स व्यवस्था तैयार करेंगे : डॉ. मांडविया

केंद्रीय मंत्री ने ऐतिहासिक घुड़सवार पदक विजेताओं को किया सम्मानित

❍ कहा, पिछले दशक में हमारे खेल इकोसिस्टम में जबरदस्त बदलाव आया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को एफईआई एशियन इक्वेस्ट्रियन (घुड़सवारी) चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया।

पटाया में हुए इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट से छह सदस्यीय भारतीय दल ने टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में कुल 5 पदक जीतकर देश के लिए इतिहास रच दिया। इवेंटिंग में आशीष लिमये ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक और टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। ड्रेसाज में श्रुति बोरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन रजत पदक हासिल किए—दो व्यक्तिगत और एक टीम इवेंट में। टीम के अन्य सदस्य शशांक सिंह कटारिया व शशांक कनमुड़ी (इवेंटिंग) और दिव्याकृति सिंह व गौरव पुंडीर (ड्रेसाज) थे। एथलीटों को सम्मानित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत अब उन खेलों में भी सफलता हासिल कर रहा है, जिनमें पहले वैश्विक स्तर पर हमारी उपस्थिति बेहद सीमित थी। उन्होंने कहा, यह 10 साल पहले वाला भारत नहीं है। पिछले दशक में हमारे खेल इकोसिस्टम में जबरदस्त बदलाव आया है। सरकार खिलाड़ी और उसके पदक के बीच आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। हम भारत में इक्वेस्ट्रियन के लिए अनुकूल स्पोर्ट्स व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि खिलाड़ियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए न जाना पड़े। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार एक साल के भीतर देश में एक क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए घोड़ों की आवाजाही में लंबे समय से आ रही समस्या का समाधान करेगा।

तीन रजत पदक विजेता श्रुति बोरा ने मंत्री के त्वरित कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा, जैसे ही हमने अपनी चिंताएं साझा कीं, उन्होंने तुरंत इक्वाइन डिजीज-फ्री जोन पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें केवल कुछ खिलाड़ियों को बाहर भेजने के बजाय पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। जब यह व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तो भारत में ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी—सब कुछ बेहद सुगम हो जाएगा।

बीसीसीआई और एडिडास ने ऑल न्यू टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्सी का अनावरण किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

फोटोः हि.स.

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर, एडिडास ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) के साथ साझेदारी में ऑल-न्यू टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्सी का अनावरण किया है। यह जर्सी सबसे पहले इस स्टेडियम में मौजूद लोगों ने देखी, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के वन डे इंटरनेशनल मैच में नाटकीय रूप से अपने असली आकार में यह जर्सी पेश की गई। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट के साथ पूरा स्टेडियम जश्न के माहौल में डूब गया था।

एडिडास इंडिया के जीएम, विजय चौहान ने कहा कि एडिडास हमारे क्रिकेटर्स को विश्वस्तर का परफॉर्मेंस गियर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर जर्सी उस खिलाड़ी या फैन की कहानी कहती है, जो इसे पहनता है। हर जर्सी एक विरासत प्रदर्शित करती है। बीसीसीआई के साथ हमें भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच इस जर्सी का अनावरण करने की खुशी है। हम चाहते हैं कि आगामी टूर्नामेंट्स, खासकर वर्ल्ड कप में देश इन रंगों को गर्व के साथ पहने। भारतीय क्रिकेटर और एडिडास एथलीट, रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट फैन के रूप में उत्साह बढ़ाने से लेकर देश के लिए ट्रॉफी लाने तक इस खेल ने मुझे पूरे जीवन की यादें दी हैं। अब मैं एक नए अध्याय की शुरूआत कर रहा हूँ, लेकिन गर्व अभी भी वही है। यह नई टीम इंडिया जर्सी हमें याद दिलाती है कि चाहे आप स्टैंड में हों या मैदान पर, हम सभी एक ही रंग पहनते हैं और भारत के लिए एक ही सपने में यकीन रखते हैं। जर्सी के इस ऐतिहासिक अनावरण से एडिडास और बीसीसीआई का फैन्स को गेम के करीब लाने और इस जर्सी को खिलाड़ियों, फैन्स और देश के बीच एकजुटता का शक्तिशाली प्रतीक बनाने का लक्ष्य उजागर होता है। इस नई जर्सी में बोल्ड और पुराने डिजाइन तत्वों के साथ आधुनिक उच्च-परफॉर्मेंस सिल्हुएट है। इसकी प्रेरणा 1990 की पट्टीदार जर्सी से ली गई है। किट में रेट्रो ट्विस्ट के साथ आधुनिक इनोवेशन के पैटर्न पेश किए गए हैं, जबकि नेकलाईन 2024 टी20 विश्व कप विजेता जर्सी से ली गई है। गर्म मौसम से निपटने के लिए इसमें एडिडास के लेटेस्ट क्लाइमाकूल+ मटेरियल के साथ बॉडी-मैप्ड 3डी इंजीनियर्ड मैकेनिकल स्ट्रेच फैब्रिक्स दिया गया है, जो पसीने को ज्यादा तेजी से सोखता है, जिससे खिलाड़ी ज्यादा लंबे समय तक सूखा हुआ महसूस करते हैं।

एशियन कप आर्म रेसलिंग के लिए टीम इंडिया की कप्तान बनीं ओनम गाम्नो

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

प्रो पंजा लीग ने एशियन कप आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप के लिए टीम इंडिया की कप्तान के रूप में अरुणाचल प्रदेश की ओनम गाम्नो और उपकप्तान के रूप में छत्तीसगढ़ के पैरा-एथलीट श्रीमंत झा को नियुक्त किया है। श्रीमंत झा पैरा-आर्म रेसलिंग के जाने-माने खिलाड़ी हैं, जो टीम में समावेश और प्रेरणा के प्रतीक माने जा रहे हैं।

यह नियुक्ति उस समय हुई है, जब अरुणाचल प्रदेश हाल की घटनाओं के चलते देशभक्ति की भावना से सराबोर है। 27 वर्षीय कप्तान ओनम गाम्नो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के मेबो थाना क्षेत्र के नगोपोक गांव की रहने वाली हैं। वह देश की सबसे सफल आर्म रेसलर्स में से एक हैं। उन्होंने 2024 में मुंबई में हुए एशियन कप में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, 2025 की नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और 2023 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीते थे। उनकी उपलब्धियां पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उपकप्तान श्रीमंत झा हाल ही में हंगरी पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड कप में रजत पदक जीत चुके हैं। विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों के लिए वह दृढ़ संकल्प और संघर्ष की मिसाल हैं। उनकी उपस्थिति टीम के नेतृत्व में नई ऊर्जा और मजबूती का संचार करती है। कप्तान ओनम गाम्नो ने कहा, भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा हर कदम देश के नाम है। मैं पूरी ताकत से खेलूंगी और तिरंगे को गौरवान्वित करूंगी।

हेजलवुड को रिहैब के दौरान नई चोट, एड़ी में 'लो-ग्रेड' इंजरी से एशेज में वापसी संदिग्ध

ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एक बार फिर चोट की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अब लो-ग्रेड अकिलीस इंजरी हुई है। इसके बाद एशेज सीरीज के बचे हुए मुकाबलों में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गाबा में जारी डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने हेजलवुड की फिटनेस को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी किया। बयान में कहा गया, जोश हेजलवुड ने इस सप्ताह अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से रिकवरी के दौरान अकिलीस में दर्द की शिकायत की। यह लो-ग्रेड समस्या है और अगले सप्ताह उनसे दोबारा रनिंग और बॉलिंग शुरू करने की उम्मीद है। हालांकि हेजलवुड के ठीक होने का स्पष्ट टाइमलाइन तय नहीं है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी एड़ी की समस्या कितनी जल्दी सुधरती है। गौरतलब है कि हेजलवुड पिछले महीने शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते हुए हैमस्ट्रिंग चोटिल हुए थे। शुरुआती स्कैन में सब सामान्य था, लेकिन दोबारा जांच में चोट की पुष्टि हुई, जिसके चलते वे एशेज सीरीज के पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए।

केआईयूजी 2025: एलपीयू के सरताज तिवाना ने 50 मीटर राइफल 3पी में जीता गोल्ड

एजेंसी (हि.स.)
जयपुर

फोटोः हि.स.

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के निशानेबाज सरताज तिवाना ने पिछले एक साल से पिता की गंभीर बीमारी और मानसिक थकान का सामना करते हुए भी अपने जज्बे और मेहनत से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2025 में 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम इवेंट में भी एलपीयू को गोल्ड दिलाया।

मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम वर्ष के छात्र सरताज जानते थे कि राजस्थान में हो रहे केआईयूजी 2025 उनके लिए सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप से पहले आत्मविश्वास वापस पाने का महत्वपूर्ण अवसर है। 23 वर्षीय सरताज ने दबाव को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन कर अपना गोल्डन स्ट्रीक बरकरार रखा। उन्होंने कहा, आज का परिणाम वही है जिसकी मैंने कल्पना की थी। पिछले एक साल में कई बदलावों से गुजर रहा था। नेशनल चैंपियनशिप से पहले ऐसा माइलस्टोन मिलना बेहद उत्साहजनक है। यह मेरे लिए यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथी बार था और मैं हर बार पोडियम पर रहा हूं- इस रिकॉर्ड को टूटने नहीं देना चाहता था। सरताज ने बोर्डिंग स्कूल में शूटिंग शुरू की थी और तब से वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2023 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथा स्थान और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज जीता। पिछले साल जुलाई में उनके सपनों को बड़ा झटका लगा, जब उनके पिता कुलतेज तिवाना को न्यूमोनाइटिस और 'लंग चिकनपॉक्स' जैसी दुर्लभ समस्या के कारण वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इस कारण सरताज को दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छोड़कर मोहाली लौटना पड़ा। पिता की गंभीर हालत ने उनके मानसिक संतुलन और अभ्यास पर गहरा असर डाला।

प्रीमियर लीगः मागासा के देर से किए गोल ने बचाई वेस्ट हैम की लाज

एजेंसी (हि.स.)
मैनचेस्टर

फोटोः हि.स.

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गुरुवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड से 1-1 से ड्रा खेला। उसे प्रीमियर लीग में पाँचवें स्थान पर पहुँचने का मौका गंवाना पड़ा। इस नतीजे के साथ ही वेस्ट हैम अभी भी रिलीगेशन जोन में बना हुआ है। पहले हाफ में दोनों टीमों का खेल बेहद फीका रहा और कोई भी गोल नहीं हो सका। 58वें मिनट में दीओगो डालोट ने गोल दागकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को बढ़त दिलाई। लेकिन मैच खत्म होने से सात मिनट पहले वेस्ट हैम के सऊंगौतू मागासा ने शानदार बराबरी गोल कर दिया, जिसके बाद अंतिम सीटी पर यूनाइटेड प्रशंसकों की ओर से हूटिंग सुनाई दी।

अंक तालिका में मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि वेस्ट हैम 12 अंकों के साथ 18वें स्थान पर बना हुआ है और 17वें स्थान पर मौजूद लीड्स यूनाइटेड से दो अंक पीछे है। मैच की शुरूआत के पहले आधे घंटे में वेस्ट हैम ने गेंद पर अच्छा नियंत्रण रखा लेकिन कोई वास्तविक खतरा नहीं बना सके। इसके बाद यूनाइटेड ने लय पकड़ी। ब्रायन मब्यूमो के दूर से लगाए गए लूपिंग शॉट को गोलकीपर अल्फोंस अरियोला ने शानदार तरीके से बार के ऊपर पहुंचाया।

आमद डायलो ने बॉक्स में गेंद भेजी, जिस पर जोशुआ ज़िर्कज़ी ने थाई से शॉट लगाया, लेकिन आरोन वान-बिसाका ने गोललाइन पर शानदार बचाव किया। कुछ ही देर बाद ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट पोस्ट के बाहर से निकल गया।

दर्पण विशेष

महापरिनिर्वाण दिवस 2025: संविधान निमार्ता आंबेडकर की याद में राष्ट्रीय श्रद्धांजलि

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान निमार्ता के इस स्मृति दिवस का उद्देश्य समानता, न्याय और सामाजिक बदलाव के उनके संदेश को दोहराना है। चैत्यभूमि से पूरे देश तक यह दिन सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों को सशक्त करता है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

6 दिसंबर 1956 की सुबह ने भारत को झकझोर दिया था, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, संविधान निमार्ता, सामाजिक क्रांति के प्रतीक और करोड़ों वंचितों की आशा, ने इसी दिन संसार को अलविदा कहा। उनके निधन के बाद 6 दिसंबर को 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा, जो आज भारतीय समाज के लिए केवल स्मृति का दिन नहीं, बल्कि समानता की दिशा में सतत संघर्ष का संकल्प भी है। डॉ. आंबेडकर का अंतिम संस्कार 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के दादर स्थित चैत्यभूमि में बौद्ध रीति से किया गया। उनके लाखों अनुयायी हर वर्ष 6 दिसंबर को चैत्यभूमि पहुंचकर उनके विचारों, संघर्षों और योगदान को याद करने लगे। यह परंपरा धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई और महाराष्ट्र सरकार सहित कई राज्यों ने इस दिन को आधिकारिक स्मृति दिवस के रूप में मान्यता देना शुरू किया। समय के साथ, यह दिन भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। महापरिनिर्वाण दिवस केवल आंबेडकर के निधन का दिन नहीं है, यह उस विचारधारा का प्रतीक है जिसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को भीतर तक हिलाया। यह दिन समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति डॉ. आंबेडकर की प्रतिबद्धता को स्मरण करता है। यह समाज को याद दिलाता है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है। उनकी बौद्ध दीक्षा के बाद फैली 'नवयान बौद्ध' धारा को भी यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। देशभर में इस दिन पर सेमिनार, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, संविधान-पाठ, और शांति रैलियों का आयोजन किया जाता है। डॉ. आंबेडकर की शिक्षाएं आज भी समाज के हर वर्ग को प्रेरित कर रही हैं, चाहे वह महिलाओं के अधिकार हों, दलितों की समान भागीदारी या आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चैत्यभूमि में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ यह साबित करती है कि आंबेडकर केवल इतिहास नहीं भारत के वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शन हैं। सामाजिक चेतना बढ़ाना, शिक्षा और अवसरों में समानता को प्रोत्साहित करना, और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मजबूती देना इन्हीं लक्ष्यों की पुनर्स्मृति इस दिन होती है। कई राज्य सरकारें 6 दिसंबर को राजकीय श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाती हैं। महाराष्ट्र में यह दिन सार्वजनिक अवकाश भी होता है। सरकारी प्रतिष्ठानों में संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को दोहराते हुए डॉ. आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जाती है। केंद्र और राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों को जनमानस तक पहुँचाना है। डॉ. आंबेडकर का जीवन संघर्ष, अध्ययन और न्याय की निरंतर खोज का प्रतीक था। महापरिनिर्वाण दिवस केवल उनके निधन का स्मरण नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना का प्रतिबिंब है जहाँ हर नागरिक समान अधिकारों के साथ खड़ा हो सके।

अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक

बीआर अंबेडकर अपने जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कुछेक महान विद्वान लोगों में से एक थे। उनके पास अलग अलग 32 विषयों की डिग्रियां थीं। एलफिंस्टन कॉलेज मुंबई से बीए करने के बाद वह एमए करने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। वहीं से पीएचडी भी की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी किया। ग्रेज इन (बैरिस्टर-एट-लॉ) किया। एलफिंस्टन कॉलेज में वह अकेले दलित छात्र थे।

किताबे पढ़ने का जबरदस्त शौक

डॉ. अंबेडकर को खूब किताबे पढ़ने का शौक था। उनके पास किताबों का विशाल व बेहतरीन संग्रह था। जॉन गुंथेर ने इनसाइड एशिया में लिखा है कि 1938 में अंबेडकर के पास 8000 किताबे थीं। उनकी मृत्यु के समय वो 35000 हो गई थीं।

पिता की 14 संतान लेकिन सिर्फ अंबेडकर को मिला पढ़ने का मौका

अंबेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। इस वजह से भी अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उस समय एक दलित और अछूत मानी जाने वाली जाति के बच्चे के लिए स्कूल जाकर पढ़ना संभव नहीं था। अंबेडकर को स्कूल में अन्य बच्चों जितने अधिकार नहीं थे। उन्हें अलग बैठाया जाता था। वह खुद पानी भी नहीं पी सकते थे। ऊंची जाति के बच्चे ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालते थे।

क्या था असली नाम

अंबेडकर का असल नाम अंबावाडेकर था। यही नाम उनके पिता ने स्कूल में दर्ज भी कराया था। लेकिन उनके एक अध्यापक ने उनका नाम बदलकर अपना सरनेम 'अंबेडकर' उन्हें दे दिया। इस तरह स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबेडकर दर्ज हुआ। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में अंबेडकर की शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई। उस समय अंबेडकर की उम्र महज 15 साल थी।

महापरिनिर्वाण दिवस का महत्व

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की परिवर्तनकारी विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस का गहरा महत्व है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण माना जाता है, जिसका संस्कृत शब्द 'मृत्यु के बाद निर्वाण' है। परिनिर्वाण को कर्म, कर्म और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति माना जाता है। यह बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है। समाज सुधारक बाबासाहेब आंबेडकर के लिए, बुद्ध उनकी विचारधारा और विचारों के बहुत करीब थे। बाबासाहेब को भारत में अस्पृश्यता के सामाजिक अभिशाप को मिटाने में उनके महान प्रभाव के कारण बौद्ध गुरु माना जाता था। आंबेडकर के प्रशंसक और अनुयायी मानते हैं कि वे भगवान बुद्ध के समान ही प्रभावशाली थे, यही कारण है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पंचकूला करेगा 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की मेजबानी

40 से 50 हजार लोग इस आयोजन के बनेंगे साक्षीः उपायुक्त

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

पंचकूला 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) 2025 की मेजबानी करेगा। सेक्टर-5 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों छात्र, युवा शोधकर्ता और विज्ञान प्रेमी भाग लेंगे।

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने यह जानकारी शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ. शिव कुमार शर्मा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव, नगराधीश जागृति, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण रामदास तथा आईआईटीएम के समन्वयक डॉ. अनुप महाजन उपस्थित थे।

इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन 6 दिसंबर को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 दिसंबर, रविवार को आयोजित प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष 9 दिसंबर को समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

उपायुक्त ने कहा कि यह पंचकूला के लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए पंचकूला को चुना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। देशभर से आने वाले छात्रों के रहने-खाने, परिवहन तथा कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई है। पंचकूला के स्कूली छात्रों और विज्ञान में रुचि रखने वाले नागरिकों को भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे विज्ञान की नवीनतम प्रगति और शोध कार्यों से रूबरू हो सकें।

इस वर्ष इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान से समृद्धि-आत्मनिर्भर भारत थीम पर होगा आयोजित

आईआईटीएम पुणे के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव ने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है और इसका 11वां संस्करण इस वर्ष पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस वर्ष का थीम 'विज्ञान से समृद्धि - आत्मनिर्भर भारत' रखा गया है। इसके तहत विभिन्न सब-थीमों पर इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि विज्ञान और तकनीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में कैसे सहायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान छात्र देशभर से आए विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकेंगे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित शोध संस्थान आमजन के लिए प्रदर्शनी में स्टॉल लगाएंगे, जिनका अवलोकन कोई भी नागरिक कर सकता है।

खेल सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मिली नई पहचान

महापौर कुलभूषण गोयल ने वार्ड-1 में विकास कार्यों का किया शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नगर निगम पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने शुक्रवार को वार्ड नंबर 1 में करोड़ों रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। महापौर ने सबसे पहले ने स्टेडियम में तैयार किए गए आधुनिक लॉन टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। खेल सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण वातावरण में अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य हर सेक्टर और हर वार्ड में खेलों को बढ़ावा देना और बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

इसी क्रम में महापौर ने वार्ड में स्थित श्मशान घाट पर बनाए गए शौचालय परिसर का भी लोकार्पण किया, जिससे वहां आने वाले लोगों को स्वच्छता और सुविधा का बेहतर वातावरण मिलेगा। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 1 में निर्मित नए स्वागत द्वार का भी उद्घाटन किया गया, जो क्षेत्र की पहचान और सुंदरता में इजाफा करेगा।

महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक लगभग 400 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जिनसे शहरवासियों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि निगम का प्रमुख ध्यान नागरिक सुविधाओं के विस्तार, खेल संरचनाओं के निर्माण, सफाई व्यवस्था बेहतर करने और हर वार्ड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर रहा है। बच्चों और युवाओं के लिए बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, क्रिकेट और अन्य खेल सुविधाएं पार्कों में उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है।

वार्ड पार्षद नरेंद्र पाल सिंह लुबाना ने महापौर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पंचकूला में कई प्रशंसनीय विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग पांच वर्षों में वार्ड नंबर 1 में करोड़ों रुपये के काम पूरे किए गए हैं, जिनसे स्थानीय लोगों को बेहतर सड़कें, पार्क, नालियां, स्ट्रीट लाइट और खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोग भाजपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं और आने वाले समय में भी पंचकूला का चहुंमुखी विकास भाजपा की ही अगुवाई में होगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी महापौर और पार्षद का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र की भौतिक स्थिति और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने किया नेचर कैम्प थापली का भ्रमण

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को राज्य की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और संस्कृति से रूबरू करवाने के उद्देश्य से दो दिवसीय विशेष भ्रमण कार्यक्रम के तहत श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को नेचर कैम्प थापली का भ्रमण किया।

युवा कल्याण समन्वयक नरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार युवा वर्ग के कल्याण और जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर रेंज ऑफिसर संजय ने विद्यार्थियों को नेचर कैम्प थापली की संरचना और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने ट्रैकिंग के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों, सुरक्षा उपायों एवं वन विभाग द्वारा की जा रही संरक्षण पहल के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

रेंज ऑफिसर संजय ने बताया कि नेचर कैम्प थापली की शुरूआत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, ताकि युवा प्रकृति के महत्व को समझें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनें और जंगलों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण से सीधे जुड़े अनुभव प्राप्त कर सकें।

उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर एसडी कॉलेज में नैक आधारित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

नैक के आउटकम-बेस्ड एक्रेडिटेशन पर विशेषज्ञों ने रखे विचार, 120 से अधिक प्रतिभागियों की रही भागीदारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में शुक्रवार को पीएम उषा स्कीम (रूसा) के तहत 'नैक आउटकम-बेस्ड एक्रेडिटेशन के तहत ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी एश्योरेंसः अवसर और चुनौतियाँ' विषय पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से आए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकताओं ने नैक के आउटकम-बेस्ड फ्रेमवर्क के तहत गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्थागत सुधार और नई चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल्स सहित 120 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस की शुरूआत जीजीडीएसडी कॉलेज सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉ. अनिरुद्ध जोशी के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा में क्वालिटी एश्योरेंस प्रक्रियाओं के निरंतर विकास और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर दिया।

एकेडेमिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए नामी वक्ताओं ने करिकुलम रीडिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन रणनीति, आउटकम-बेस्ड असेसमेंट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और फैकल्टी एम्पावरमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी, क्योंकि नैक अब एक अधिक गतिशील और डेटा-आधारित एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क की ओर अग्रसर है। उद्घाटन सत्र में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) जगदीप सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, जहाँ मापनीय लर्निंग आउटकम्स को संस्थागत विकास का मुख्य आधार माना जाए।

यह कार्यक्रम प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा के धन्यवाद भाषण के साथ खत्म हुआ, जिसमें उन्होंने एकेडमिक क्वालिटी और इनोवेशन के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। इस कॉन्फ्रेंस को जीजीडीएसडी कॉलेज की आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉ. मोनिका सचदेवा और इंग्लिश विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर गगनप्रीत वालिया के नेतृत्व में कोऑर्डिनेट किया गया।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने उपायुक्त को लगाया फ्लैग

पंचकूला। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे के अवसर पर विंग कमांडर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी संजय कुमार राय ने सेक्टर-1 स्थित डीसी ऑफिस में उपायुक्त सतपाल शर्मा को फ्लैग लगाया। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे की उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने कहा कि पूरे देश में आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे के तौर पर मनाया जा रहा है। यह उन शहीदों और वर्दी वाले जवानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने देश की इज्जत की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। देश के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। साथ ही, शहीदों के लिए हमारी तारीफ का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उन जिंदा हीरो के लिए कम समय है जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना फर्ज निभाते हुए घायल हो गए या उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए जिन्हें वे अपना ख्याल खुद रखने के लिए पीछे छोड़ गए। देश ने जो अलग-अलग युद्ध लड़े हैं और बॉर्डर पार से चल रहे आतंकवाद और बगावत से लड़ते हुए, उन्होंने बताया कि जीत हासिल करने के दौरान, हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने कीमती जानें गंवाई हैं और लगातार गंवा रहे हैं, साथ ही कई लोग विकलांग भी हुए हैं। परिवार के मुखिया की मौत पर परिवार को जो सदमा लगता है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे जो जवान विकलांग हैं, उन्हें देखभाल और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है ताकि वे अपने परिवार पर बोझ न बनें और इसके बजाय इज्जत की जिंदगी जी सकें। इसके अलावा, ऐसे एक्स-सर्विसमैन भी हैं जो कैंसर, दिल की बीमारियों और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और जो इलाज का ज्यादा खर्च नहीं उठा सकते।